■ वैशाख कृष्णा - 4 ■ संवत 2082 ■ वर्ष - 12 ■ अंक - 258 ■ पृष्ठ - 8 ■ रु. 5/- चेन्नई » शुक्रवार » 18-04-2025 ■ www.dakshinbharat.com ■ Email : chennai@dakshinbharat.com

# दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

4 संस्कृत और संस्कृति के संरक्षण के लिए हो कार्य : बागड़े

6 नई विश्व संरचना में विरासत एवं विकास का समन्वय अपेक्षित

7 'वागले की दुनिया' में सुगंधा मिश्रा की हुई एंट्री

## फर्स्ट टेक

### रूस ने कीव में भारतीय कंपनी के गोदाम पर हमला करने का यूक्रेन का आरोप खारिज किया

नई दिल्ली/भाषा। रूस ने बृहस्पतिवार को यूक्रेन के उन आरोपों को खारिज किया कि रूसी सेना ने कीव में एक भारतीय दवा कंपनी के गोदाम पर हमला किया। रूसी दूतावास ने आशंका जताई है कि यूक्रेनी वायु रक्षा मिसाइल भारतीय फार्मा कंपनी 'कुसुम' के गोदाम पर गिरी होंगी जिससे आग लग गई। भारत में यूक्रेनी दूतावास ने शनिवार को कहा कि रूसी मिसाइल ने भारतीय दवा कंपनी कुसुम के गोदाम को निशाना बनाया और मॉस्को यूक्रेन में भारतीय व्यवसायों को ''जानबूझकर'' निशाना बना रहा है। नई दिल्ली में यूक्रेन के दूतावास द्वारा लगाए गए ''आरोपों'' के जवाब में, रूसी दूतावास ने एक बयान में कहा कि रूसी सशस्त्र बलों ने 12 अप्रैल को कुसुम हेल्थकेयर के गोदाम पर न तो हमला किया और न ही हमला करने की कोई योजना बनाई।

### रूस ने अफगान तालिबान पर लगा प्रतिबंध हटाया

**मॉस्को/एपी।** रूस के उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अफगानिस्तान के तालिबान पर लगा प्रतिबंध हटा दिया, जिसे दो दशक से अधिक समय पहले आतंकवादी समूह घोषित किया गया था। यह कदम तालिबान के लिए एक कूटनीतिक जीत है, जिसे 2003 में रूस ने आतंकवादी संगठनों की सूची में डाल दिया था तथा रूसी कानून के तहत उससे किसी भी प्रकार का संपर्क दंडनीय था। अभियोजक जनरल के कार्यालय के अनुरोध पर न्यायालय का यह फैसला पिछले वर्ष पारित एक कानून के बाद आया है, जिसके अनुसार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित किए जाने के कदम को न्यायालय द्वारा निलंबित किया जा सकता है।

### लेबनान ने इजराइल पर रॉकेट दागने के संदेह में कई लोगों को हिरासत में लिया

बेरूत/एपी। लेबनान की सेना के मुताबिक पिछले महीने इजराइल पर रॉकेट दागने के संदेह में लोगों के एक समूह को हिरासत में लिया गया है। लेबनानी सेना ने बुधवार देर रात जारी एक बयान में कहा कि उसने कई लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें कई फलस्तीनी भी शामिल हैं, जो मार्च के अंत में इजराइल की ओर दो अलग-अलग हमलों में रॉकेट दागने में शामिल थे, जिसके जवाब में इजराइल ने लेबनान के कुछ हिस्सों पर भीषण हवाई हमला किया था। लेबनान में सक्रिय चरमपंथी समूह हिजबुल्ला ने इन हमलों में अपना हाथ होने से इनकार किया था।

| 18-04-2025 सूर्यास्त | 19-04-2025 सूर्योदय |
|---|---|
| 6:22 बजे | 6:54 बजे |

| BSE | NSE |
|---|---|
| 78,553.20 | 23,851.65 |
| (+1,508.91) | (+414.45) |

| सोना | चांदी |
|---|---|
| 9,312 रु. | 102,000 रु. |
| (24 कैरेट) प्रति ग्राम | प्रति किलो |

# बढ़ती महंगाई के लिए मोदी जिम्मेदार : सिद्दरामय्या

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**बेंगलूरु/भाषा।** कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा।

राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की 'जन आक्रोश यात्रा' के जवाब में कांग्रेस ने बेंगलूरु के फ्रीडम पार्क में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन में शामिल सिद्दरामय्या ने सवाल किया कि क्या मौजूदा मूल्य वृद्धि मोदी की ओर से 2014 में सत्ता में आने से पहले किए गए अच्छे दिन के वादे का नतीजा है।

मुख्यमंत्री ने भाजपा पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में दो रुपए प्रति लीटर और रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए प्रति

सिलेंडर की वृद्धि करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, देश में बढ़ती महंगाई के लिए नरेन्द्र मोदी जिम्मेदार हैं। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि 'अच्छे दिन' आएंगे? क्या 'अच्छे दिन' आ गए?

सिद्दरामय्या ने कहा कि 2014 से पहले सोने की कीमत 28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जो अब बढ़कर 95,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की सरकार के दौरान चांदी की कीमत 43,000 रुपए प्रति किलोग्राम थी और अब यह 94,000 रुपए प्रति किलोग्राम को पार कर गई है।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, 2014 से पहले एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 59 रुपए थी, लेकिन अब यह बढ़कर 87 रुपए हो गई है।

# मौजूदा वक्फ में पांच मई तक कोई बदलाव नहीं : उच्चतम न्यायालय

■ न्यायालय ने वक्फ अधिनियम की वैधता पर जवाब के लिए केंद्र को सात दिन का समय दिया

■ अदालत ने कहा कि केवल पाँच रिट याचिकाओं पर विचार किया जाएगा और शेष को निपटाया हुआ माना जाएगा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**नई दिल्ली/एजेन्सी।** उच्चतम न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए कहा कि मौजूदा वक्फ में अगली सुनवाई तक कोई बदलाव नहीं होने चाहिए। न्यायालय मामले की अगली सुनवाई पांच मई को करेगा।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार तथा न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद कहा, हम नहीं चाहते कि स्थिति बदले। पांच साल (इस्लाम का अभ्यास) जैसे प्रावधान हैं, जिन पर हम रोक नहीं लगा रहे हैं।

पीठ के समक्ष मेहता ने निवेदन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार सात दिन के भीतर जवाब दाखिल करेगी और अगली तारीख तक परिषद या बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगली तारीख तक उपयोगकर्ताओं द्वारा वक्फ का स्वरूप नहीं बदलेगा, हालांकि उन्होंने तर्क दिया कि अदालत को वक्फ संशोधन अधिनियम, 1995 पर अप्रत्यक्ष रूप से रोक लगाकर कठोर रुख नहीं अपनाना चाहिए। अदालत ने मेहता का बयान दर्ज किया और जवाब दाखिल करने की अनुमति दी। शीर्ष अदालत ने सरकार के जवाब पर याचिकाकर्ताओं को पांच दिन के भीतर जवाब दाखिल करने की अनुमति दी। पीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए पांच मई, 2025 की तारीख मुकर्रर की।

सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा कि केवल पाँच रिट याचिकाओं पर विचार किया जाएगा और शेष को निपटाया हुआ माना जाएगा, क्योंकि 100 या 120 याचिकाओं पर विचार करना असंभव है।

अदालत ने आदेश दिया कि 1995 के वक्फ अधिनियम और 2013 में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को सूची में अलग से दिखाया जाएगा। अदालत ने केंद्र के लिए कनु अग्रवाल को नोडल वकील नियुक्त किया। शुरुआत में, मेहता ने कहा कि वह बुधवार को अदालत द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदालत को केवल कुछ धाराएँ पढ़कर कानून पर रोक नहीं लगानी चाहिए। उन्होंने कहा, कई संशोधन हुए, समितियाँ बनीं और लाखों लोगों ने प्रतिनिधित्व किया। गाँव छीने जा रहे हैं और निजी संपत्तियाँ वक्फ के तौर पर छीनी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर अदालत पक्षों की बात सुन ले तो कुछ नहीं बदलेगा।

# मानसरोवर यात्रा जल्द बहाल होगी

## चीन के साथ विमान सेवा पर बनी 'सैद्धांतिक' सहमति : भारत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**नई दिल्ली/भाषा।** भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के जल्द ही दोबारा बहाल होने की उम्मीद है और इसकी तैयारियां की जा रही हैं।

भारत और चीन पिछले वर्ष अक्टूबर में हुए समझौते के तहत डेमचोक और देपसांग के दो शेष टकराव बिंदुओं पर सैनिकों की वापसी पूरी करने के बाद संबंधों को सुधारने के प्रयासों के तहत कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर विचार कर रहे हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत और चीन दोनों देशों के

बीच उड़ान सेवाएं फिर से शुरू करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं और प्रासंगिक तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है।

कैलाश मानसरोवर यात्रा और उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू करने का कदम भारत और चीन द्वारा पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चार साल से अधिक समय से चल रहे सैन्य गतिरोध की वजह से प्रभावित संबंधों को सुधारने के प्रयासों का हिस्सा है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ''हम शीघ्र ही कैलाश मानसरोवर यात्रा पर सार्वजनिक सूचना जारी करेंगे और यात्रा जल्द ही दोबारा शुरू होने की संभावना है। उन्होंने कहा, ''यात्रा इस वर्ष होगी और हम इसकी तैयारियां कर रहे हैं। जल्द ही जनता के लिए अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

कैलाश मानसरोवर यात्रा 2020 के बाद से नहीं हुई है।

जायसवाल ने उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू करने के बारे में कहा, ''सैद्धांतिक रूप से, दोनों देश इस बात पर सहमत हो गए हैं कि उड़ान सेवा फिर से शुरू होगा।

# क्वाड का भविष्य उज्ज्वल है : भारत

**नई दिल्ली/भाषा।** भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि क्वाड का भविष्य उज्ज्वल है और वह इस वर्ष के अंत में समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। क्वाड चार देशों का एक समूह है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान शामिल हैं। यह समूह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। पिछले कुछ वर्षों में क्वाड ने समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और संपर्क (कनेक्टिविटी) के क्षेत्रों समेत हिंद-प्रशांत क्षेत्र की कुछ सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई पहल की हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, ''क्वाड का भविष्य उज्ज्वल है। हालांकि उन्होंने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया कि क्वाड शिखर सम्मेलन कब होगा।

# सुरक्षा बलों के त्याग और तपस्या के कारण ही हम सुरक्षित : शाह

■ आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व में पांचवें नंबर का अर्थतंत्र बना है। कुछ ही सालों में देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**आबू रोड़ (सिरोही)/एजेन्सी।** केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सशस्त्र बलों के सुरक्षाकर्मी माइनस 46 डिग्री सेल्सियस से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में अपने जीवन का स्वर्णकाल देकर हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं और उनके त्याग-तप और बलिदान के कारण आज हम सुरक्षित हैं।

शाह गुरूवार को सिरोही जिले के आबूरोड स्थित ब्रह्मकुमारीज हैडक्वार्टर शांतिवन में आयोजित सुरक्षा बल के कर्मियों के लिए आंतरिक जागृति के माध्यम से आत्म-सशक्तीकरण विषयक राष्ट्रीय संवाद के शुभारम्भ के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने सुरक्षाकर्मियों के मन, आत्मा और शरीर को शांति का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में कार्य करने के लिए ब्रह्माकुमारीज़ संस्था को साधुवाद दिया।

उन्होंने कहा कि योग और अध्यात्म से मन-बुद्धि, शरीर और आत्मा को एकरूप करके ज्ञान से प्रगति के रास्ते पर मानवता को आगे ले जाने की भारत की बहुत पुरानी परंपरा है। हम इस परंपरा को आज भी समग्र विश्व में पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, विश्व को सबसे पहले भारत ने दी।

शाह ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व में पांचवें नंबर का अर्थतंत्र बना है। कुछ ही सालों में देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि जब आजादी का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा तब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में हर क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी परंपराओं में पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व की भावना की ओर ले जाने की क्षमता है, हर मानव के अंदर मौजूद आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने की शक्ति और हर जीवन को सद्वृत्ति की नई राह पर ले जाने की शक्ति है। इन परम्पराओं को इतनी ही तेजी के साथ आगे ले जाना यह भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रह्माकुमारीज ने अपने त्याग, तपस्या और तेज से दुनिया भर में सादगी, संयम और सहयोग का एक अद्भुत वातावरण खड़ा करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि ब्रह्माकुमारी संस्था में मनुष्य के अंदर की सद्वृत्ति को जाग्रत करने का प्रयास अनेक वर्षों से किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप मन को अगाध शांति का अनुभव यहां आकर होता है और मैंने आज स्वयं भी यह महसूस किया है।

# 'न्यायपालिका भारत के राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकती, 'सुपर संसद' के रूप में कार्य कर रही'

■ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की कार्यशैली पर उठाये सवाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**नई दिल्ली/भाषा।** उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बृहस्पतिवार को न्यायपालिका द्वारा राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए समयसीमा निर्धारित करने और 'सुपर संसद' के रूप में कार्य करने को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय लोकतांत्रिक ताकतों पर 'परमाणु मिसाइल' नहीं दाग सकता।

धनखड़ ने न्यायपालिका के प्रति यह कड़ी टिप्पणी राज्यसभा

के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए की। कुछ दिन पहले ही उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए समयसीमा तय की थी।

उन्होंने ने कहा, '' हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यपालिका के कार्य करेंगे, जो सुपर संसद के रूप में कार्य करेंगे और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है।

उपराष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को पूर्ण शक्तियां प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 142 को ''न्यायपालिका को चौबीसों घंटे उपलब्ध लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल'' करार दिया। उन्होंने कहा, ''अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है और (जो) न्यायपालिका के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध है।

संविधान का अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को अपने समक्ष किसी भी मामले में ''पूर्ण न्याय'' सुनिश्चित करने हेतु आदेश जारी करने की शक्ति देता है। इस शक्ति को उच्चतम न्यायालय की ''पूर्ण शक्ति'' के रूप में भी जाना जाता है।

## मिशन मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक

epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

### अजीब लोग

सोच रहे हैं लोग यहां कुछ,
बोल रहे हैं कुछ ही और।
चेहरे पर चेहरे रखने का,
चला आजकल ऐसा दौर।
जीते जी बोले ना उनसे,
बाद मृत्यु के करते शोर।
इस दुनिया का अजब चलन है,
करिए आप जरा सा गौर।।

# पाकिस्तान 1971 के अत्याचार के लिए माफी मांगे : बांग्लादेश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

ढाका/भाषा। बांग्लादेश ने ''ऐतिहासिक रूप से अनसुलझे मुद्दों'' को उठाया और 1971 के अत्याचारों के लिए पाकिस्तान से सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की। बांग्लादेश ने यह मुद्दा बृहस्पतिवार को यहां 15 वर्षों में पहली बार पाकिस्तान के साथ विदेश सचिव स्तर की वार्ता के दौरान उठाया।

बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 1971 में स्वतंत्र होने से पहले की संयुक्त परिसंपत्तियों में से अपने

हिस्से के रूप में 4.3 अरब अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने को भी कहा।

बांग्लादेश के विदेश सचिव जशीम उद्दीन ने अपनी पाकिस्तानी समकक्ष आमना बलूच के साथ विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) के बाद संवाददाताओं से कहा, ''हमने पाकिस्तान के साथ ऐतिहासिक रूप से अनसुलझे मुद्दों को उठाया है।'' बांग्लादेश ने यह मुद्दा ऐसे समय उठाया है जब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार 27 को दो दिवसीय दौरे पर ढाका आ रहे हैं। उद्दीन ने संवाददाताओं से कहा कि जिन मुद्दों को उठाया गया है, उनमें ''यहां फंसे हुए पाकिस्तानियों की वापसी, अविभाजित संपत्तियों का न्यायसंगत बंटवारा, 1970 के चक्रवात के पीड़ितों के लिए भेजी गई विदेशी सहायता राशि का हस्तांतरण और 1971 में तत्कालीन पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए नरसंहार के लिए औपचारिक रूप से सार्वजनिक माफी'' शामिल है।

# अनुसंधानकर्ताओं को सौरमंडल के बाहर जीवन के 'सबसे पुख्ता संकेत' मिले

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**नई दिल्ली/भाषा।** अनुसंधानकर्ताओं ने कहा है कि एक बाह्यग्रह पर समुद्री जीवों द्वारा उत्पादित अणुओं के संकेत मिले हैं, जो सौरमंडल के बाहर जीवन का ''अब तक का सबसे पुख्ता संकेत'' हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि इस संबंध में और अधिक आंकड़ों की जरूरत है। इस संबंध में अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि 'के2-18 बी' सौरमंडल के बाहर का एक ग्रह है जो पृथ्वी से 8.5 गुना अधिक विशाल है, जहां पहले मीथेन (सीएच4) और कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) जैसे कार्बन युक्त अणु पाए गए हैं। यह बाह्यग्रह पृथ्वी से 120 प्रकाश वर्ष दूर है और 'के2-18' तारे की परिक्रमा करता है।

इस अध्ययन में, ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं के नेतृत्व में नासा की जेम्स वेब स्पेस दूरबीन से प्राप्त आंकड़ों और तस्वीरों का विश्लेषण किया गया तथा 'डाइमिथाइल सल्फाइड' और 'डाइमिथाइल डाइसल्फाइड' के संकेतों का पता लगाया जो कि समुद्री कवक जैसे सूक्ष्मजीवों द्वारा पृथ्वी पर उत्पादित होते हैं।

अनुसंधान टीम ने एक बयान में कहा कि ये अणु ''इस बात का अब तक का सबसे पुख्ता संकेत हैं कि हमारे सौर मंडल के बाहर किसी ग्रह पर जीवन मौजूद हो सकता है। हालांकि के2-18बी पर इनका निर्माण कैसे हुआ, यह अब भी अज्ञात है। प्रमुख अनुसंधानकर्ता एवं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में खगोल भौतिकी और बाह्यग्रहीय विज्ञान के प्रोफेसर निक्कू मधुसूदन ने हालांकि कहा कि परिणाम उत्साहजनक हैं, लेकिन किसी अन्य ग्रह पर जीवन पाए जाने का दावा करने से पहले अधिक आंकड़ों पर काम करना अहम है।

उन्होंने कहा कि यद्यपि वे आशावादी हैं, फिर भी के2-18बी पर पहले से अज्ञात रासायनिक प्रक्रियाएं कार्य कर रही हो सकती हैं, जो इन प्रेक्षणों का कारण हो सकती हैं।

# मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डालेगी : भाजपा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**नई दिल्ली/भाषा।** भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया और किसानों की जमीन हड़पी, उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ईमानदार सरकार सलाखों के पीछे डालेगी।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगर गांधी परिवार ने जनता के पैसे से अपना खजाना भरा है तो उनसे एक-एक पैसा वसूला जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड मामले में कथित तौर पर 988 करोड़ रुपए के धनशोधन के लिए यहां एक विशेष अदालत में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। इस बीच, व्यवसायी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाद्रा 2008 के हरियाणा भूमि सौदे में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए बृहस्पतिवार को लगातार तीसरे दिन ईडी के समक्ष पेश हुए।

भाटिया ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार का संकल्प भ्रष्टाचार को खत्म करना, भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डालना और किसानों को उनकी हड़पी गई जमीन वापस दिलाना है। अगर गांधी परिवार ने जनता के पैसे से अपना खजाना भरा है तो उनसे एक-एक पैसा वसूला जाएगा।

उन्होंने कहा, रॉबर्ट वाद्रा को लगता है कि वह देश के कानून से ऊपर हैं। उन्हें यह एहसास नहीं है कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एक ईमानदार सरकार है, जिसके तहत जांच एजेंसियां अब 'पिंजरे में बंद' तोता नहीं हैं।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मोदी सरकार के तहत केंद्रीय जांच एजेंसियां ईमानदार बाज़ हैं और वे भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसती हैं और यह भी सुनिश्चित करती हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर बाहर आए लोगों को जेल भेजा जाए। कांग्रेस ने बुधवार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को प्रतिशोध की राजनीति बताया।

वाद्रा ने बुधवार को 'पीटीआई-भाषा' से कहा कि उन्हें गांधी परिवार का हिस्सा होने के कारण निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि देश के लोग जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं करते।

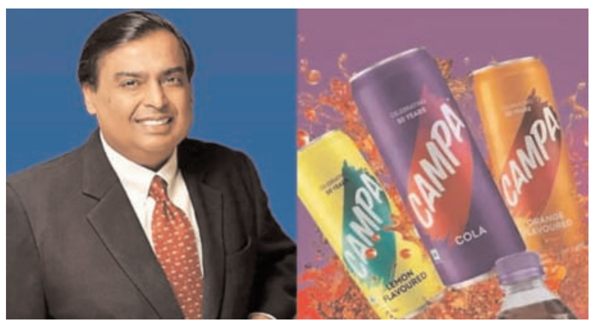



# रिलायंस अपने कैम्पा ब्रांड के लिए बिहार में 1,000 करोड़ रुपए के निवेश से नया बॉटलिंग संयंत्र खोलेगी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**नई दिल्ली/भाषा।** उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की एफएमसीजी इकाई रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (आरसीपीएल) अपने शीतल पेय ब्रांड कैम्पा का बिहार में एक नया बॉटलिंग संयंत्र खोलेगी।

रिपोर्ट के अनुसार, आरसीपीएल के स्वामित्व वाले ब्रांड का बिहार के बेगूसराय जिले में 35 एकड़ जमीन पर एक नया संयंत्र होगा, जहां वह लगभग 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसकी पुष्टि करते हुए सरकारी एजेंसी, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बीआईएडीए) ने 'एक्स' पर बताया कि यह भूखंड ईपीआईसी एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड को आवंटित किया गया है, जो कैम्पा कोला का उत्पादन और वितरण करने वाली कंपनी है। आगामी इकाई में बॉटलिंग और विनिर्माण दोनों ही तरह के काम एकीकृत होंगे। यह कैम्पा कोला की आक्रामक वृद्धि रणनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसमें पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अपने कदमों का विस्तार करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। दो माह पहले असम में इसी तरह के एक संयंत्र की शुरुआती की गई थी। इस साल फरवरी में, आरसीपीएल ने असम के गुवाहाटी में नए संयंत्र का उद्घाटन किया, जिससे पूर्वोत्तर भारत में कैम्पा ब्रांड की उपस्थिति मजबूत हुई। अगस्त, 2022 में कैम्पा कोला का अधिग्रहण करने के बाद तेजी से बढ़ते शीतल पेय बाजार में प्रवेश करने वाली रिलायंस, आपूर्ति शृंखला, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और बॉटलिंग संयंत्र के रूप में आवश्यक बुनियादी ढांचा स्थापित करके देश भर में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रही है।

# भारतीय अर्थव्यवस्था तीन साल में जर्मनी, जापान को पीछे छोड़ देगी: नीति आयोग के सीईओ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

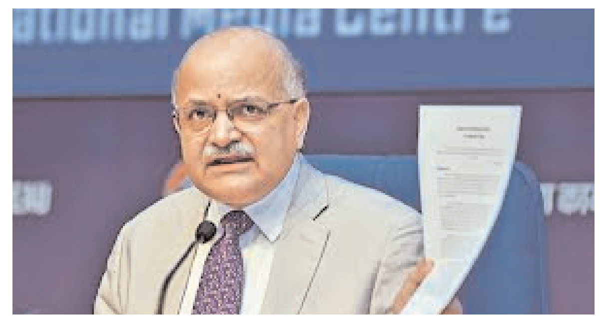

**नई दिल्ली/भाषा।** नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले तीन साल में जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ देगी और 2047 तक यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है।

सुब्रह्मण्यम ने यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत दुनिया के लिए शिक्षा का केंद्र बन सकता है, क्योंकि अन्य सभी चीजों से परे लोकतंत्र इसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा, '' फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगले वर्ष के अंत तक हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। उसके बाद वाले साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था का आकार वर्तमान में 4,300 अरब अमेरिकी डॉलर है। उन्होंने कहा, '' हम तीन वर्ष में जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ देंगे। 2047 तक हम दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (30,000 अरब अमेरिकी डॉलर) बन सकते हैं।

सुब्रह्मण्यम ने विधि और लेखा कंपनियों सहित सभी भारतीय फर्मों से विश्व में अग्रणी बनने की आकांक्षा रखने का आग्रह किया। नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि मध्यम आय वाले देशों की समस्याएं, कम आय वाले देशों की समस्याओं से बेहद अलग हैं। उन्होंने कहा, '' यह गरीबों को भोजन देने या लोगों को कपड़े उपलब्ध कराने के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि आप ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था कैसे बनें। सुब्रह्मण्यम ने कहा कि दुनिया ने कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी...जहां जनसंख्या घटेगी।

उन्होंने दावा किया कि जापान 15,000 भारतीय नर्सों तथा जर्मनी 20,000 स्वास्थ्यकर्मियों की सेवाएं ले रहा है, क्योंकि उनके पास ऐसे पेशेवर लोग नहीं हैं। वहां पारिवारिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं। सुब्रह्मण्यम ने कहा, '' भारत विश्व भर में कामकाजी आयु वर्ग के लोगों का एक स्थिर आपूर्तिकर्ता होगा...यह हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी।

## प्रधानमंत्री मोदी को 'विक्ट्री डे' समारोह के लिए आमंत्रित किया गया, जवाब का इंतजार है: रूस

**मॉस्को/भाषा।** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को नौ मई को रूस की राजधानी मॉस्को में होने वाले 'विक्ट्री डे' समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है लेकिन भारत की ओर से इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। रूस के राष्ट्रपति भवन 'क्रेमलिन' के एक शीर्ष सहयोगी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

रूस नौ मई को द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर विजय का जश्न मनाता है और इस वर्ष उसने 80वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेने के लिए चुनिंदा मित्र देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है। इन नेताओं में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग भी शामिल हैं, जिन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। 'रशियन स्टेट टीवी' ने क्रेमलिन के विदेश सहयोगी यूरी उशाकोव के हवाले से कहा, ''प्रधानमंत्री को नौ मई के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन अभी तक हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

# कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए : भाजपा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**नई दिल्ली/भाषा।** भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि नेशनल हेराल्ड मामला ''धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार एवं धन शोधन का एक स्पष्ट मामला है'' और राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाने के लिए कांग्रेस को आड़े हाथ लिया।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सरकार द्वारा परमार्थ उपयोग के लिए नेशनल हेराल्ड को दी गई संपत्तियों का निजी लाभ के लिए इस्तेमाल करने के कारण अपने नेताओं के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। पुरी ने कांग्रेस के इस आरोप को खारिज कर दिया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार विपक्षी दल के नेताओं को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा, ''नेता अपने ही कार्यकर्ताओं को गुमराह कर रहे हैं। अगर उन्हें विरोध करना है, तो उन्हें अपने नेतृत्व के खिलाफ विरोध करना चाहिए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी, दोनों के पास यंग इंडियन में 76 प्रतिशत हिस्सेदारी होने के तथ्य की ओर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने कहा कि कंपनी ने 50 लाख रुपए की मामूली राशि के लिए एसोसिएटेड जर्नल्स के 99 प्रतिशत शेयर हस्तांतरित कर दिए।

# विहिप ने हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने की मांग की

**पणजी/भाषा।** विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने पश्चिम बंगाल में नये वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के बाद मुर्शिदाबाद जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की बृहस्पतिवार को मांग की। विहिप महासचिव मिलिंद परांडे ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनका संगठन हिंसा की निंदा करने के लिए देश के सभी जिलों में प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा, ''हम वक्फ अधिनियम के विरोध के बहाने हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। संशोधित वक्फ अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान 11 और 12 अप्रैल को मुर्शिदाबाद के कुछ इलाकों में हिंसा भड़क उठी थी। हिंसा में कम से कम तीन लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हो गये थे। इसके बाद इलाके में पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने कहा है कि हिंसा के कारण सैकड़ों महिलाओं को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, जिनमें से कई ने भागीरथी नदी पार कर पड़ोसी मालदा जिले में शरण ली।

## मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश का कार्यकाल बढ़ा

**मुंबई/भाषा।** बंबई उच्च न्यायालय ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई कर रहे विशेष एनआईए न्यायाधीश ए के लाहोटी को नासिक स्थानांतरित करने का आदेश देने के कुछ दिन बाद अब उनका कार्यकाल 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है।

लाहोटी का नाम उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा पहले जारी की गई न्यायाधीशों की वार्षिक स्थानांतरण सूची में शामिल था।

इस महीने की शुरुआत में जारी अधिसूचना के अनुसार, उन्हें नासिक की अदालत में स्थानांतरित किया था और स्थानांतरण आदेश ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद नौ जून को अदालतें फिर से खुलने के बाद प्रभावी होना था। हालांकि, एक नई अधिसूचना में कहा गया है कि लाहोटी का कार्यकाल 31 अगस्त तक स्थगित कर दिया गया है ताकि वह इस मामले में फैसला सुना सकें, जिसकी सुनवाई अंतिम चरण में है। मुंबई से 200 किलोमीटर दूर उत्तर महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल पर रखे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से छह लोगों की मौत हुई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे। इस मामले में कथित संलिप्तता के लिए भारतीय जनता पार्टी की नेता और भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और पांच अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई जारी है।

# मनरेगा मजदूरी 400 रुपए और कार्यदिवस 150 किया जाए: खरगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**नई दिल्ली/भाषा।** कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ग्रामीण विकास संबंधी संसद की स्थायी समिति की अनुंशसाओं का उल्लेख करते हुए बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत दैनिक मजदूरी को 400 रुपए किया जाए।

देश के ग्रामीण नागरिकों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। वर्तमान में कुछ राज्यों में मजदूरी दर 370 रु प्रति दिन है, जबकि कुछ में यह 234 प्रति दिन भी है।

कांग्रेस सांसद सप्तगिरि उलाका की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि मनरेगा के तहत मजदूरी को पूरे देश में प्रतिदिन 400 रुपए किया जाए और कार्य दिवस को साल में 150 दिन किया जाए। खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''ऐसा लगता है कि जनविरोधी मोदी सरकार ने मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने से इनकार कर दिया है। यह मनरेगा श्रमिकों के अधिकारों पर कुल्हाड़ी चलाना है। उन्होंने कहा कि हाल ही में संयुक्त संसदीय समिति ने मनरेगा श्रमिकों की रोज़ाना मजदूरी को 400 रुपए प्रतिदिन करने की सिफारिश की थी। खरगे ने इस बात का उल्लेख किया कि वर्ष 2023 में बनी अमरजीत सिन्हा समिति ने भी मजदूरी बढ़ाने और मनरेगा का बजट बढ़ाने का सुझाव दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि ''ग़रीब विरोधी'' मोदी सरकार एक के बाद एक मनरेगा मज़दूरों पर जुल्म ढाने पर उतारू है।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया, ''क़रीब सात करोड़ पंजीकृत कामगारों को मनरेगा से 'आधार' आधारित भुगतान की शर्त लगा बाहर करना हो, या फिर 10 सालों में मनरेगा बजट का पूरे बजट के हिस्से में सब से कम आवंटन करना हो, मोदी सरकार ने मनरेगा पर लगातार चोट मारने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा देश के सबसे ग़रीब परिवारों के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा लाया गया रोज़गार की गारंटी का अधिकार है। खरगे ने कहा, ''हम अपनी दो मांगों पर अडिग हैं। मनरेगा श्रमिकों के लिए रोज़ाना 400 रुपए की न्यूनतम मजदूरी तय की जाए और साल में कम से कम 150 दिन का काम मिले।

## महाराष्ट्र में पहली से पांचवीं कक्षा तक के लिए हिंदी अनिवार्य तीसरी भाषा; मनसे ने की निंदा

**मुंबई/भाषा।** महाराष्ट्र सरकार ने दो भाषाओं का अध्ययन कराने की परंपरा से हटकर राज्य भर के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पहली से पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ना अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने राज्य सरकार के इस निर्णय की निंदा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस फैसले का पुरजोर विरोध करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इसे लागू न किया जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत नए पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन में पहली से पांचवीं कक्षा के लिए त्रि-भाषा फॉर्मूले को लागू किया गया है। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूली शिक्षा के लिए एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुसार तैयार किए गए नए पाठ्यक्रम के चरणबद्ध कार्यान्वयन की योजना का ऐलान किया है। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मनसे इस निर्णय को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम केंद्र सरकार के हर चीज को 'हिंदीकृत' करने के मौजूदा प्रयासों को इस राज्य में सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, ''हिंदी राष्ट्र भाषा नहीं है। यह देश की अन्य भाषाओं की तरह राजभाषा है। महाराष्ट्र में इसे शुरू से ही क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? आपका जो भी त्रि-भाषा फॉर्मूला है, उसे सरकारी मामलों तक ही सीमित रखें, शिक्षा में न लाएं। मनसे प्रमुख ने कहा, ''आपने महाराष्ट्र पर दूसरे क्षेत्र की भाषा क्यों थोपना शुरू कर दिया है? भाषायी क्षेत्रीयकरण के मूल सिद्धांत को कमजोर किया जा रहा है। ठाकरे ने कहा, ''हम हिंदू हैं, पर हिंदी नहीं! अगर आप महाराष्ट्र को हिंदी के रूप में चित्रित करने की कोशिश करेंगे तो महाराष्ट्र में विवाद होना तय है।

## रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पीएनबी पर जुर्माना लगाया

**मुंबई/भाषा।** भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामकीय अनुपालन में कुछ खामियों के लिए कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) पर जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक पर 'बैंक ऋण वितरण के लिए ऋण प्रणाली पर दिशानिर्देश' और 'ऋण और अग्रिम – वैधानिक और अन्य प्रतिबंध' पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए 61.4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एक अन्य बयान में, रिजर्व बैंक ने कहा कि 'अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)' के कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर 38.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

# बीआरएस ने हैदराबाद विवि के निकट पेड़ काटे जाने के संबंध में 'उल्लंघनों' की जांच की मांग की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**हैदराबाद/भाषा।** भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता केटी रामा राव ने हैदराबाद विश्वविद्यालय से सटी भूमि पर कथित रूप से बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई को लेकर तेलंगाना सरकार पर हमला तेज करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि अगर केंद्र सरकार वास्तव में इस मुद्दे को लेकर चिंतित है तो उसे कथित उल्लंघनों और वित्तीय अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच का आदेश देना चाहिए।

रामा राव ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है तो उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) जैसी केंद्रीय एजेंसियों से जांच का आदेश देना चाहिए। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष रामा राव ने यहां संवाददाताओं से कहा, अपनी पसंद की जांच एजेंसी चुनें। हम केंद्र सरकार से जवाब मांगते हैं। उन्होंने उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की ओर से, वित्तीय अनियमितताओं के बारे में पहले ही चिंता जताए जाने के बावजूद केंद्र की निष्क्रियता पर सवाल उठाया और स्वतंत्र जांच का समर्थन किया। रामा राव ने कहा कि समिति ने राय दी है कि विचाराधीन भूमि प्रथम दृष्टया विश्वविद्यालय के स्वामित्व में प्रतीत होती है। समिति ने उच्चतम न्यायालय से तेलंगाना औद्योगिक अवसंरचना निगम (टीजीआईआईसी) द्वारा भूमि का व्यावसायिक रूप से दोहन करने की आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने का भी समर्थन किया।

## महाराष्ट्र : नांदेड़ में सड़क किनारे स्टॉल पर 'पानी पुरी' खाने से 31 छात्र बीमार

**छत्रपति संभाजीनगर/भाषा।** महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में खाद्य विषाक्तता के संदिग्ध मामले में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के 31 छात्रों को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये छात्र सड़क किनारे एक दुकान पर 'पानी पुरी' खाने के बाद बीमार पड़ गए थे। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के मुताबिक प्रभावित छात्र शहर के तीन शैक्षणिक संस्थानों – स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, एसजीजीएस कॉलेज और एक नर्सिंग कॉलेज के हैं।

अस्पताल के एक अधिकारी ने कहा, '' डॉ. शंकरराव चव्हाण सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में सुबह चार बजे के बाद से 31 छात्रों को भर्ती कराया गया। छात्रों को उल्टी, जी मिचलाने और बेचैनी की शिकायत के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इन छात्रों ने सड़क किनारे एक दुकान से 'पानी पुरी' खाई थी। उन्होंने बताया कि मेडिकल जांच के बाद छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल के विभिन्न वार्डों में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

महाराष्ट्र में 'पानी पुरी' एक लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है, जिसे उत्तर भारत में 'गोलगप्पा' के नाम से जाना जाता है।

# कांग्रेस को इस तरह खत्म नहीं किया जा सकता, सोनिया और राहुल को लोगों का समर्थन : चेन्निथला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**मुंबई/भाषा।** अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है।

चेन्निथला ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से कांग्रेस पार्टी को खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जनता का समर्थन प्राप्त है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड मामले में कथित तौर पर 988 करोड़ रुपए के धनशोधन मामले में दिल्ली की एक विशेष अदालत में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की शिकायत नौ अप्रैल को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई थी।

चेन्निथला ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, '' कांग्रेस को कमजोर करने के लिए यह राजनीतिक प्रतिशोध है। कांग्रेस को इस तरह खत्म नहीं किया जा सकता। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जनता का समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस इस मुद्दे पर अपना आंदोलन तेज करेगी और 19 अप्रैल को इस सिलसिले में दिल्ली में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है।

# जो लोकतंत्र बेचेंगे, वे अगले जन्म में ऊंट, भेड़, बकरी, कुत्ता और बिल्ली बनेंगे: भाजपा विधायक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**इंदौर/भाषा।** मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की विधायक उषा ठाकुर ने कहा है कि जो व्यक्ति लोकतंत्र बेचेंगे, वे अगले जन्म में ऊंट, भेड़, बकरी, कुत्ता और बिल्ली जैसे जानवर बनेंगे। उन्होंने चुनावों के दौरान मतदाताओं द्वारा धन, शराब और उपहारों के लालच में वोट डालने की प्रवृत्ति पर नाराजगी जताते हुए अपने महू विधानसभा क्षेत्र के हासलपुर गांव में यह बात बुधवार को एक सभा के दौरान कही। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बृहस्पतिवार को प्रसारित हुआ।

वीडियो में ठाकुर कहते हुए सुनाई दे रही हैं, ''भाजपा सरकार की लाड़ली बहना योजना और किसान सम्मान निधि जैसी कितनी योजनाओं के माध्यम से हर हितग्राही के खाते में हजारों रुपए आते ही हैं। उसके बाद भी यदि 1,000-500 (रुपए) में वोट बिक जाए, तो फिर यह मनुष्यों के लिए डूब मरने की बात है। उन्होंने सभा में मौजूद ग्रामीणों से अपील की कि वे लोकतंत्र की रक्षा करें। भाजपा विधायक ने कहा, ''लोकतंत्र में हम वोट डालने जाते हैं, तो कोई देखता है क्या? तब आप अकेले होते हैं और आपके साथ केवल परमपिता परमात्मा होते हैं, तो किसी ने कुछ ले-दे भी लिया, तो ले लो भाई....पर वोट डालते समय अपना ईमान मत गंवाओ। वोट तो भाजपा को ही देना जो राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की सेवा करती है।

अपने बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वालीं ठाकुर, राज्य की पूर्व काबीना मंत्री हैं। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा, ''ये जो गिलासधारियों के पैसे, साड़ी, गिलास और दारू लेकर तटस्थ हुए, सब अपनी डायरी में लिख लेना कि वे पक्के तौर पर अगले जन्म में ऊंट, भेड़, बकरी, कुत्ते और बिल्ली बनने वाले हैं। जो लोकतंत्र बेचेंगे, वे ये ही बनने वाले हैं, यह बात पक्के तौर पर लिख लेना। भगवान से मेरी सीधी बातचीत है, मेरा विश्वास करना। इस बयान को लेकर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर ठाकुर ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को समझाकर उन्हें जागरूक करने के लिए ये बातें कही थीं। उन्होंने कहा, ''लोकतंत्र हमारा प्राण है। सरकार संविधान के प्रावधानों के मुताबिक हितग्राहियों की जिंदगी बेहतर करने के लिए कई योजनाएं संचालित करती है और पूरे 12 महीने जनता की सेवा करती है। ऐसे में चुनावों के वक्त अगर कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति में धन, शराब या अन्य सामग्री लेकर अपना वोट बेचेगा, तो यह अक्षम्य अपराध है। ठाकुर ने अपने बयान को उचित ठहराते हुए कहा, ''हमें अपने कर्मों के आधार पर अगला जीवन मिलता है। अगर हमारे कर्म खराब होंगे, तो अगले जन्म में हमें फिर मनुष्य योनि थोड़े ही मिलेगी। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता मृणाल पंत ने कहा कि भाजपा विधायक का बयान न केवल उनकी ''दकियानूसी सोच'' को दिखाता है, बल्कि यह महू क्षेत्र में सत्तारूढ़ दल के नेताओं की अंदरूनी खींचतान की ओर भी साफ इशारा करता है।

# कांग्रेस, माकपा, आईयूएमएल ने वक्फ मुद्दे पर शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**तिरुवनंतपुम/कोच्चि/मुंबई।** मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने उच्चतम न्यायालय के उस फैसले का बृहस्पतिवार को स्वागत किया, जिसमें केंद्र सरकार से कहा गया है कि वह 1995 के वक्फ अधिनियम के तहत पंजीकृत वक्फ संपत्तियों को पांच मई तक गैर-अधिसूचित नहीं करेगी। शीर्ष अदालत ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सरकार से यह भी कहा कि इस अवधि में केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। माकपा की केरल इकाई के सचिव एमवी गोविंदन ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप देश के धर्मनिरपेक्ष समूहों के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि यह फैसला वक्फ अधिनियम में संशोधन करने के केंद्र के मनमाने धर्मनिरपेक्षता-विरोधी निर्णय के खिलाफ एक प्रभावी बचाव है। गोविंदन ने उम्मीद जताई कि शीर्ष अदालत का अंतिम फैसला उनके पक्ष में होगा।

वहीं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि संसद में पारित कानून पर सर्वोच्च न्यायालय की ओर से रोक लगा दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम आदेश के जरिये देश को बड़ा संदेश दिया है कि वक्फ अधिनियम में संशोधन को लेकर विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) और कांग्रेस ने संसद में जो चिंताएं जाहिर की थीं, वे सही थीं। कोच्चि में संवाददाताओं से मुखातिब वेणुगोपाल ने दावा किया कि शीर्ष अदालत ने कहा है कि यह अधिनियम संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है।

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान वही सवाल उठाए, जो विपक्ष ने संसद में उठाए थे। वेणुगोपाल ने कहा, यह अंतरिम आदेश हमारी, लोकतंत्र और संविधान की जीत है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला ने मुंबई में संववादाताओं से कहा कि यह आदेश विवादास्पद कानून के खिलाफ उनकी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के रुख की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 संविधान के खिलाफ है। चेन्निथला ने कहा, यह आदेश एक अच्छा कदम है। हम इसका स्वागत करते हैं। शीर्ष अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है और केंद्र सरकार से एक सप्ताह में (संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर) अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। केंद्र को सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पूछे गए सवालों का जवाब देना चाहिए। कोच्चि में आईयूएमएल के राष्ट्रीय महासचिव पीके कुन्हालीकुट्टी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम उपाय के तौर पर अधिनियम के कुछ प्रावधानों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है और यह दर्शाता है कि मामले की सुनवाई निष्पक्ष तरीके से की जा रही है।

कुन्हालीकुट्टी ने कहा, अब तक तो सब ठीक है। यह आदेश अंतरिम रोक की प्रकृति का है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उक्त आदेश सामान्य कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और यह देखना होगा कि अंतिम फैसला क्या होगा। शीर्ष अदालत ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र को बृहस्पतिवार को सात दिन का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच मई की तारीख तय की।

## तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने 1,882 करोड़ रुपये के सिफी डेटा सेंटर परिसर का किया उद्घाटन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**चेन्नई।** तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने 1,882 करोड़ रुपये की लगात से बने डेटा सेंटर परिसर का बृहस्पतिवार को उद्घाटन किया। इसका निर्माण सिफी ने किया है। सरकार ने बयान में कहा, सिरुसेरी के पास स्थापित यह सुविधा करीब 1,000 लोगों के लिए रोजगार के प्रत्यक्ष अवसर उत्पन्न करेगी। यह 130 मेगावाट का कृत्रिम मेधा (एआई) से लैस डेटा सेंटर परिसर होगा। बयान के अनुसार, सिफी टेक्नोलॉजीज अन्य के अलावा एकीकृत इंटरनेट समाधान और संचार सेवाएं, डेटा सेंटर अवसंरचना प्रदान करती है।

इसमें कहा गया, मुख्यमंत्री स्टालिन ने अत्याधुनिक डेटा सेंटर का उद्घाटन किया। कंपनी की 2027 तक चेन्नई में करीब 13,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना है। इस पहल के लिए समझौते पर जनवरी, 2024 में यहां आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। मुख्यमंत्री स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार अधिक रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने और राज्य को 2030 तक 1,000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की इच्छुक है। इसलिए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई कदम उठा रही है।

बयान में कहा गया है कि तमिलनाडु भी द्रमुक सरकार के तहत आर्थिक वृद्धि में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य ने वित्त वर्ष 2024-25 में दशक की सर्वश्रेष्ठ 9.69 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की है। डेटा सेंटर के उद्घाटन के दौरान उद्योग मंत्री टी.आर.बी राजा भी मौजूद थे।

## मद्रास उच्च न्यायालय ने पश्चिमी घाट में 28 प्रकार की प्लास्टिक वस्तुओं पर लगाया प्रतिबंध

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**चेन्नई।** मद्रास उच्च न्यायालय ने पश्चिमी घाट क्षेत्र में 28 प्रकार की प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। न्यायमूर्ति एन सतीश कुमार और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने जी. सुब्रमणिया कौशिक और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया।

पीठ ने तमिलनाडु सरकार को मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें यह शर्त हो कि पश्चिमी घाट (जिसमें नीलगिरी और कोडैकनाल शामिल हैं) में प्रतिबंधित वस्तुओं के परिवहन/वितरण के लिए किसी भी वाहन का उपयोग नहीं किया जाएगा। यदि कोई वाहन इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे जब्त कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पीठ ने कहा कि जो दुकानदार या अन्य व्यक्ति गैर-जैवनिम्नीकरणीय प्लास्टिक फॉइल/रैपर में पैक खाद्य सामग्री का वितरण करते हैं, उन्हें सामग्री को जैविक (बायोडिग्रेडेबल) पदार्थों में स्थानांतरित करना होगा। स्थानीय निकायों को बिना किसी शुल्क के कागज के थैले उपलब्ध कराने होंगे, जिनकी लागत 'ग्रीन फंड' से वापस की जा सकती है। पत्तों आदि से बने जैविक विकल्प भी वितरित किए जा सकते हैं।

पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि जिला कलेक्टरों और स्थानीय निकायों समेत सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि क्षेत्र में 'एटीएम, आरओ प्लांट और अन्य तरीकों' के माध्यम से पेयजल की उपलब्धता बनी रहे। उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को इन सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और 6 जून, 2025 तक स्थिति की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

## तमिलनाडु : स्वतंत्रता सेनानी धीरन चिन्नामलई को उनकी जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**चेन्नई।** तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और अन्य नेताओं ने बृहस्पतिवार को स्वतंत्रता सेनानी धीरन चिन्नामलई को उनकी 269वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। रवि ने कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र धीरन चिन्नामलई को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। स्टालिन और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने यहां गिंदी में चिन्नामलई के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। गिंदी में स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा भी स्थापित है।

तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (टीएनसीसी) अध्यक्ष के. सेल्वापेरुन्थगई सहित अन्य लोग भी इस मौके पर यहां मौजूद थे। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) महासचिव और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एडप्पाडी के. पलानीस्वामी और पार्टी नेताओं ने भी बाद में कार्यक्रम स्थल पर चिन्नामलई को पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल रवि ने चिन्नामलई को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें 'एक महान स्वतंत्रता सेनानी और मां भारती का वीर सपूत' बताया। राजभवन के सोशल मीडिया पोस्ट में उनके हवाले से कहा गया, चिन्नामलई ब्रिटिश औपनिवेशिक अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध की एक बड़ी ताकत थे। अटूट साहस, रणनीतिक दूरदर्शिता और अडिग संकल्प के साथ उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की मजबूत नींव रखी।

रवि ने कहा, हमारे इतिहास के एक निर्णायक क्षण में, उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने विद्रोह की भावना को जगाया, जिसने उनके समकालीनों को प्रेरित किया और पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखा।

उन्होंने कहा कि चिन्नामलई की विरासत जीवित है और राष्ट्र को आत्मनिर्भर व समृद्ध विकसित भारत की ओर ले जाती है, जो उन्हीं आदर्शों पर आधारित है जिन्हें स्वतंत्रता सेनानी ने वीरता से कायम रखा। स्टालिन ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि तमिलनाडु में आज भी उपनिवेशवाद रोधी मानसिकता का एक कारण चिन्नामलई द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के बाद बोए गए बीज हैं। पलानीस्वामी ने भी चिन्नामलई के बहादुरी भरे प्रयासों की सराहना की।

## तमिलनाडु में गठबंधन सरकार के लिए कोई स्थान नहीं : अन्नाद्रमुक नेता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**चेन्नई।** अन्नाद्रमुक के वरिष्ठ नेता एम थंबीदुरई ने बृहस्पतिवार को कहा कि तमिलनाडु में गठबंधन सरकार के लिए कोई जगह नहीं है और अगर अगले साल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की जीत होती है तो पार्टी प्रमुख के. पलानीस्वामी राज्य में 'अकेले' सरकार बनाएंगे।

राज्यसभा सदस्य ने गठबंधन सरकार के बारे में संवाददाताओं के प्रश्नों के उत्तर में यह बात कही। थंबीदुरई ने कहा कि राज्य में कभी गठबंधन सरकार नहीं बनी, चाहे वह कांग्रेस के दिग्गज नेता (दिवंगत) सी राजगोपालाचारी का कार्यकाल रहा हो या के. कामराज का या द्रविड़ नेता एम जी रामचंद्रन का या एम करूणानिधि का।

उन्होंने कहा, 2026 में भी एडप्पाडियार (पलानीस्वामी) अकेले सरकार बनाएंगे और गठबंधन सरकार के लिए कोई जगह नहीं है। तमिलनाडु में कभी गठबंधन सरकार नहीं रही है। ऐसा कभी नहीं होगा।

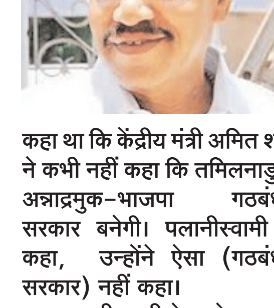

पलानीस्वामी ने बुधवार को कहा था कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक-भाजपा गठबंधन सरकार बनेगी। पलानीस्वामी ने कहा, उन्होंने ऐसा (गठबंधन सरकार) नहीं कहा।

पलानीस्वामी ने आरोप लगाया कि मीडिया ने प्रासंगिक मुद्दे को गलत समझा है जो गड़बड़ चलता है। उन्होंने मीडिया से चालें नहीं चलने का अनुरोध किया। पलानीस्वामी ने कहा कि 11 अप्रैल को शाह ने घोषणा की थी कि अन्नाद्रमुक-भाजपा गठबंधन चुनाव जीतेगा और सरकार बनेगी।

उन्होंने कहा कि इसका मतलब गठबंधन सरकार नहीं है। तमिलनाडु में, हालांकि द्रमुक और अन्नाद्रमक ने हमेशा चुनावी गठबंधन बनाए हैं लेकिन उन्होंने कभी अपने सहयोगियों के साथ सत्ता साझा नहीं की है।

## तमिलनाडु सरकार ने मंदिरों का 1,000 किलो सोना पिघलाकर 17.81 करोड़ रुपये सालाना ब्याज कमाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**चेन्नई।** तमिलनाडु के 21 मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए 1,000 किलोग्राम से अधिक सोने के सामान को पिघलाकर 24 कैरेट की छड़ों में बदल दिया गया और बैंकों में जमा कर दिया गया। सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि सोने की छड़ों के इस निवेश से उसे सालाना 17.81 करोड़ रुपये का ब्याज मिल रहा है।

मंदिरों में चढ़ाए गए सोने के ऐसे सामान, जिनका इस्तेमाल नहीं किया गया था, उन्हें मुंबई स्थित सरकारी टकसाल में पिघलाकर 24 कैरेट की छड़ों में बदल दिया गया और स्वर्ण निवेश योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में निवेश कर दिया गया।

हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ निधि विभाग के मंत्री पी के शेखर बाबू द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत नीति लेख में कहा गया, निवेश से अर्जित ब्याज का उपयोग संबंधित मंदिरों के विकास के लिए किया जाता है। योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य के तीनों क्षेत्रों के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में तीन समितियां गठित की गई हैं।

सोने की छड़ों के 31 मार्च तक के निवेश का ब्योरा देते हुए लेख में कहा गया, प्रदेश के 21 मंदिरों से प्राप्त 10,74,123.488 ग्राम शुद्ध सोने पर प्रति वर्ष 17.81 करोड़ रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, जो निवेश के समय सोने के मूल्य के अनुसार निर्धारित किया गया।

मंदिरों में से, तिरुचिरापल्ली जिले के समयपुरम में अरुलमिगु मरिअम्मन मंदिर ने निवेश योजना के लिए सबसे अधिक 4,24,266.491 ग्राम (लगभग 424.26 किलोग्राम) सोना दिया।

मानव संसाधन एवं संवर्द्धन विभाग के नियंत्रण में मंदिरों में 'अप्रयुक्त एवं अनुपयोगी' चांदी की वस्तुओं को सरकार द्वारा अनुमोदित निजी चांदी प्रगलन कंपनियों द्वारा मंदिर परिसर में तीन न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली क्षेत्रीय समितियों की उपस्थिति में शुद्ध चांदी की सिल्लियों में पिघलाने की अनुमति दी गई है। बयान के अनुसार, तदनुसार, वर्तमान में मंदिरों में बिना उपयोग की चांदी की वस्तुओं को पिघलाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

## इन्फोसिस 3.6 करोड़ डॉलर में करेगी एमआरई कंसल्टिंग का अधिग्रहण

**नयी दिल्ली।** सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनी इन्फोसिस ने बृहस्पतिवार को प्रौद्योगिकी और व्यापार परामर्श कंपनी एमआरई कंसल्टिंग का 3.6 करोड़ डॉलर (लगभग 307.4 करोड़ रुपये) के नकद सौदे में अधिग्रहण करने के लिए एक निश्चित समझौते की घोषणा की। आईटी कंपनी अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी इन्फोसिस नोवा होल्डिंग्स एलएलसी के माध्यम से परामर्श कंपनी का अधिग्रहण करेगी। अधिग्रहण चालू वित्त वर्ष (2025-26) की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में पूरा होने की उम्मीद है।

कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि अधिग्रहण की लागत 3.6 करोड़ डॉलर तक होगी, जिसमें अग्रिम भुगतान और 'अर्नआउट' (कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर भुगतान) शामिल हैं। कंपनी के बयान में कहा गया है कि इस अधिग्रहण से इन्फोसिस को ट्रेडिंग और जोखिम प्रबंधन, खासकर ऊर्जा क्षेत्र में नई क्षमताएं मिलेंगी।

इन्फोसिस ने कहा, टेक्सास के ह्यूस्टन में मुख्यालय वाली एमआरई कंसल्टिंग में 200 से अधिक पेशेवरों की टीम होगी, जिनके पास ऊर्जा/जिंस ट्रेडिंग और जोखिम प्रबंधन (ई/सीटीआरएम) मंच और माहौल में उद्योग ज्ञान, परामर्श और गहन प्रौद्योगिकी अनुभव होगा।

## विवादित टिप्पणी मामले में पुलिस तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करे : अदालत

**चेन्नई।** मद्रास उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु पुलिस को राज्य के वन मंत्री के पोनमुडी के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। पोनमुडी द्वारा दिये गए विवादास्पद बयान के कारण उन्हें पार्टी पद से हटा दिया गया था। उच्च न्यायालय ने पुलिस को चेतावनी दी कि यदि वह राज्य में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक)नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करती हैं तो वह उसके खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर अवमानना की कार्यवाही शुरू करेगा। न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा, अब अदालत ने मामले का संज्ञान ले लिया है। अगर आपके पास शिकायत नहीं भी है तो भी मामला दर्ज करें और जांच आगे बढ़ाएं। न्यायाधीश ने मामले में स्वत: संज्ञान लेकर आगे की सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तिथि निर्धारित की। पोनमुडी ने हाल ही में एक सार्वजनिक बैठक में एक यौनकर्मी के संदर्भ में शैव-वैष्णव संबंधी टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया था। उनके बयान की व्यापक पैमाने पर आलोचना हुई थी। पोनमुडी की आलोचना करने वालों में उनकी अपनी पार्टी की सांसद कनिमोई भी शामिल थीं। द्रमुक अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने पोनमुडी को पार्टी के उप महासचिव पद से हटा दिया था। हालांकि बाद में वरिष्ठ नेता ने अपनी 'अनुचित टिप्पणी' के लिए माफी मांगी थी।

## सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिका पर केंद्र सरकार और केरल के मुख्यमंत्री से जवाब तलब

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**कोच्चि।** केरल उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि विजयन ने निजी खनन कंपनी से रिश्वत ली है। याचिका में इस मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का अनुरोध भी किया गया है।

न्यायमूर्ति अमित रावल और न्यायमूर्ति पी.एम. मनोज ने केंद्र सरकार, विजयन, उनकी बेटी वीना, बेटी की बंद हो चुकी आईटी कंपनी एक्सेलॉजिक, निजी खनन कंपनी सीएमआरएल और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) समेत विभिन्न पक्षों को नोटिस जारी करके पत्रकार एम. आर अजयन की याचिका पर जवाब मांगा। उच्च न्यायालय ने जिन अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है उनमें सीएमआरएल के प्रबंध निदेशक एस. एन. शशिधरन कार्था, उनके पुत्र, पत्नी और दामाद शामिल हैं। उच्च न्यायालय ने अंतरिम निपटान बोर्ड को भी नोटिस जारी किया है तथा उसे सीएमआरएल के खिलाफ आयकर कार्यवाही के संबंध में उसके निष्कर्षों में उल्लिखित व्यक्तियों की सूची सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी।

अजयन ने दावा किया है कि सीएमआरएल के खिलाफ आयकर कार्यवाही के संबंध में अंतरिम निपटान बोर्ड ने पाया था कि खनन कंपनी ने वीना की कंपनी को पैसे दिए थे। उन्होंने अधिवक्ता शाजी चिरायथ के माध्यम से दायर याचिका में यह आरोप भी लगाया है कि कंपनी ने विजयन की बेटी की कंपनी के माध्यम से विजयन को पैसे दिए थे। याचिका में मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने की मांग की गई है। इसके अलावा सेबी को सीएमआरएल के स्टॉक और शेयरों को 'डीलिस्ट' करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने इस महीने की शुरुआत में सीएमआरएल और वीना तथा उनकी अब बंद हो चुकी आईटी कंपनी एक्सालॉजिक सहित अन्य के खिलाफ कथित 'अवैध भुगतान' घोटाले के सिलसिले में आरोपपत्र दाखिल किया था।

एसएफआईओ की कथित कार्रवाई केरल उच्च न्यायालय द्वारा कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुझालनदन की उस याचिका को खारिज करने के करीब एक सप्ताह बाद हुई जिसमें निजी खनन कंपनी सीएमआरएल और एक्सालॉजिक के बीच कथित वित्तीय लेन-देन को लेकर विजयन के खिलाफ सतर्कता जांच की मांग की गई थी। खबरों के अनुसार, एसएफआईओ जांच में खनन कंपनी के भीतर 182 करोड़ रुपये की 'धोखाधड़ी' का पता चला है, जिसमें कई अन्य लोग भी आरोपी हैं। खबरों कहा गया है कि अवास्तविक खर्चों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करके और फर्जी बिल के जरिए धोखाधड़ी की गई। एसएफआईओ जांच में कथित तौर पर पाया गया कि वीना ने बिना कोई सेवा दिए निजी खनन कंपनी से 2.7 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे। मुख्यमंत्री विजयन ने हाल ही में इस आरोप का खंडन किया था।

## कर्नाटक सरकार के आश्वासन के बाद ट्रक चालकों ने हड़ताल वापस ली

**बेंगलूरु।** कर्नाटक राज्य लॉरी मालिक एवं एजेंट संघ (एफओकेएसएलओएए) से जुड़े ट्रक चालकों ने राज्य के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी द्वारा उनकी अधिकांश मांगों पर सहमति जताने के बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली। एफओकेएसएलओएए ने सोमवार रात को कई मांगों के साथ अपनी हड़ताल शुरू की, जिसमें डीजल की कीमतों में कमी और ट्रक चालकों के समक्ष टोल संबंधी समस्याएं शामिल थीं। ट्रक चालक संगठन के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और रेड्डी के साथ बातचीत की, लेकिन वार्ता असफल रही। हालांकि, एफओकेएसएलओएए के अध्यक्ष जी आर षणमुगप्पा ने बृहस्पतिवार को रेड्डी के साथ बैठक के बाद हड़ताल वापस लेने की घोषणा की। रेड्डी ने कहा एफओकेएसएलओएए ने हड़ताल समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की है। उनके अनुसार, सरकार न तो डीजल की कीमतें कम करने पर सहमत हुई है और न ही राज्य राजमार्गों पर टोल प्लाजा हटाने पर।

## कर्नाटक सरकार जाति जनगणना रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल में चर्चा करेगी और फैसला लेगी : खरगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**विपक्ष के नेता ने रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने अब तक इसे देखा भी नहीं...**

**कलबुर्गी।** कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बृहस्पतिवार को कहा कि कर्नाटक में पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार सामाजिक-आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल में विचार-विमर्श करेगी और उचित निर्णय लेगी। सामाजिक-आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट को 'जाति जनगणना' के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने अब तक इसे नहीं देखा है।

खरगे ने यहां संवाददाताओं से कहा, यह राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है, हर राज्य अपना काम करता है। केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया। राज्य सरकार मंत्रिमंडल में चर्चा करेगी और निर्णय लेगी। मैंने रिपोर्ट नहीं देखी है। मामला राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने रिपोर्ट के विरोध के बारे में पूछे जाने पर कहा, (विरोध) हो सकता है।

मैंने अपनी राय साझा की है। जाति जनगणना पर विरोध के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की अगुवाई में कर्नाटक सरकार की एक विशेष बैठक बृहस्पतिवार को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाई गई है। कर्नाटक के दो प्रमुख समुदायों वोक्कालिगा और वीरशैव-लिंगायत समुदायों सहित विभिन्न समुदायों के लोगों ने इस सर्वेक्षण (जाति जनगणना) को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे 'अव्यवस्थित' करार दिया है। समुदायों ने इस सर्वेक्षण को खारिज कर नया सर्वेक्षण कराने की मांग की है। समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा भी जाति जनगणना सर्वेक्षण पर आपत्ति जताई गई है और सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर भी इसके खिलाफ जोरदार आवाजें उठ रही हैं।

# आजादी की शताब्दी तक हर क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा भारत : अमित शाह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे होने तक दुनिया में हर क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर पहुंचने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वसुधैव कुटुम्बकम की भावना भारत ने सबसे पहले दुनिया में दी।

शाह राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में ब्रह्माकुमारीज संस्था द्वारा 'सुरक्षा बलों के कर्मियों के लिए आंतरिक जागृति के माध्यम से आत्म-सशक्तीकरण' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संवाद को संबोधित कर रहे थे। शाह ने कहा कि भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। शाह ने कहा, हमारा देश आज विश्व में पांचवें नंबर का अर्थतंत्र बन गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही साल में हम तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनेंगे। आजादी की शताब्दी तक हम विश्व में हर क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भारतीय परंपराओं में पूरी दुनिया को विश्व बंधुत्व की भावना की ओर ले जाने की क्षमता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, हर मानव के अंदर की आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने की शक्ति हमारी परंपराओं में है। और हर जीवन को सद्बुद्धि की राह पर ले जाने की शक्ति भी हमारी परंपराओं में है। ब्रह्माकुमारीज जैसी संस्थाएं इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं।

सशस्त्र बलों के सुरक्षाकर्मियों के योगदान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, उन्हीं के त्याग, तप व बलिदान के कारण आज हम सुरक्षित हैं। वे अपने जीवन का स्वर्णकाल देकर शून्य से नीचे 46 डिग्री सेल्सियस तापमान से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस तापमान में हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। तभी हम सुरक्षित हैं।

शाह ने कहा कि सभी राज्यों की पुलिस कानून-व्यवस्था की परिस्थिति संभालकर हर निर्बल को संरक्षण देने का काम करती हैं, परंतु यह काम एक प्रकार से ढेर सारा तनाव पैदा करने वाला है। उन्होंने कहा, नींद की कमी, पानी की कमी, शांत मन की कमी, सतत हिंसा करने वालों से जूझना... ये सारी चीजें व्यक्ति के मन पर एक विशिष्ट प्रकार का असर छोड़ती है।

शाह ने कहा, उस असर से हमारे सुरक्षाकर्मियों को बाहर लाकर उनके मन, आत्मा व उनके शरीर के लिए शांति का मार्ग प्रशस्त करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। उन्होंने इस दिशा में ब्रह्माकुमारीज संस्था के प्रयासों व योगदान की सराहना की।

उन्होंने कहा कि योग और आध्यात्म से मन, शरीर, बुद्धि व आत्मा इन सबको एक रूप कर ज्ञान से प्रगति के रास्ते पर जाने के लिए और चिंतन से समस्याओं के निवारण के लिए नीतियों का सृजन करना, भारत की बहुत पुरानी परंपरा है।

उन्होंने कहा कि हम इस परंपरा को आज भी समग्र विश्व में पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना भारत ने सबसे पहले विश्व में दी और जब पूरे विश्व में लोग गुफाओं में रहते थे तब 'पूरा विश्व मेरा परिवार है' हमारे उपनिषद की इस ऋचा ने समूचे विश्व को हमारा परिवार बनाया।

शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाकर हमारी वैदिक परंपरा को, हमारे ऋषि मुनियों की सबसे अमूल्य धरोहर को समग्र विश्व को देने का काम किया है। उन्होंने कहा, विश्व में करोड़ों लोग आज योग, ध्यान व आध्यात्म के रास्ते से अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं और यह रास्ता ही आने वाले दिनों में विश्व शांति का मार्ग बनने वाला है यह मेरा दृढ़ विश्वास है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद थे।

## पंजाब के तीन तस्करों से एक क्विंटल अवैध डोडा पोस्त बरामद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

श्रीगंगानगर। राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के राजियासर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक कार से एक क्विंटल चार किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद करके पंजाब के तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने गुरुवार को बताया कि पुलिस दल ने कल शाम थर्मल कॉलोनी मस्जिद के पास रोही रायांवाली में एक संदिग्ध कार को रोककर उसकी तलाशी ली तो कार में प्लास्टिक के कट्टों में एक क्विंटल चार किलो 700 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि कार में सवार शिवदत्त उर्फ संदीप उर्फ शिवा (35), राजवीर सिंह (48) और विजय सिंह (35) को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों पंजाब के हैं। इन पर मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

# सरकारी एजेन्सियों का दुरुपयोग कर रही है केन्द्र सरकार : जूली

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अलवर। राजस्थान के अलवर में जिला कांग्रेस समिति ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को मोती डूंगरी स्थित आयकर विभाग कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से राजस्थान में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता-कार्यकर्ता शामिल हुए और उन्होंने भाजपा सरकार एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की।

इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि जब से भाजपा सत्ता में आई है, तभी से कांग्रेस के शीर्ष नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित विभिन्न वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी, आयकर आदि की कार्रवाई कर रही है और कांग्रेस नेताओं को परेशान कर रही है। ये सब कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध के चलते की

जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में आगामी समय में चुनाव होने जा रहे हैं जिसके चलते भाजपा के नेता घबरा रहे हैं और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई करवा रहे हैं।

जूली ने कहा कि ईडी का जिस तरह केन्द्र सरकार दुरुपयोग कर रही है, वह किसी से छिपा नहीं है। अभी लोकसभा में यह मामला उठा कि ईडी ने कितने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की तो सामने आया कि करीब 193 विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की गयी, जिसमें से मात्र दो नेताओं के खिलाफ चालान पेश किया गया है। इससे स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार विपक्षी पाटियों को डराने-धमकाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये जिन पर आरोप लगाते हैं, वे अगर भाजपा में शामिल हो जायें तो फिर वे नेता दूध के धुले हो जाते हैं।

अब तक किसी भी भाजपा नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई नहीं की गई। जूली ने कहा कि केन्द्र सरकार सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग करके कांग्रेस नेताओं के खिलाफ षडयंत्र रच रही है, लेकिन लोकतंत्र और देश को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एकजुटता के साथ मजबूती से लड़ेगा। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के घर 15 करोड़ रुपए मिलने के मामले पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एक न्यायाधीश के घर 15 करोड़ रुपए मिलते हैं, उनकी कौन जांच करेगा। वह पैसा कहां से आया किसने दिया। इस मामले की भी जांच की जानी चाहिए। वहां ईडी क्यों नहीं पहुंची।

# नवीकरणीय ऊर्जा में विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध : भजनलाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जैसलमेर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं बताते हुए कहा है कि राज्य सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को लेकर प्रतिबद्धता से काम कर रही है और हम सभी की सहभागिता से राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में हरित और उज्ञवल भविष्य का निर्माण करेंगे जिससे उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान की संकल्पसिद्धि हो सके। शर्मा गुरुवार को जैसलमेर जिले के पोकरण में रिन्यू पावर के 1.3 गीगावॉट पीक के सौर ऊर्जा संयंत्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि जैसलमेर की सुनहरी धरा पर स्थापित इस सोलर प्लांट से राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर किए जा रहे कार्यों को गति मिलेगी। इस सोलर प्लांट से उत्पादित समस्त बिजली राजस्थान की वितरण कंपनियों को कम दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को ऊर्जा निर्बाध रूप से मिल सकेगी तथा भविष्य की परियोजनाओं के लिए भी एक बेंचमार्क तैयार होगा। इस संयंत्र से 1500 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल और सबसे स्वच्छ ऊर्जा है। अन्य ऊर्जा स्रोतों के भंडार सीमित हैं लेकिन सौर ऊर्जा का कोई क्षय नहीं होता है, यह अक्षय ऊर्जा है। हर परिवार सौर ऊर्जा का उत्पादक बन सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादन में अभी तक अनेक कदम उठाए हैं जिनके सकारात्मक परिणाम धरातल पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान देश में सौर और अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में शीर्ष पर है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में केन्द्र सरकार ने राजस्थान को प्रथम तथा अक्षय ऊर्जा के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 4 हजार 895 मेगावाट क्षमता की परंपरागत एवं 41 हजार 883 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को ढाई लाख करोड़ रुपये के निवेश से विकसित किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार ने नई राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति जारी की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी राजकीय कार्यालयों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए छतों पर रूफ टॉप सोलर लगाने के लिए एक हजार मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट हैम मॉडल के तहत लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भी नवीकरणीय ऊर्जा के अनुकूल है। राजस्थान में 142 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं हैं। कच्चे माल की भरपूर उपलब्धता, अच्छा औद्योगिक बुनियादी ढांचा, अनुकूल भौगोलिक स्थिति और कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता प्रदेश को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के निवेशकों के लिए एक उपयुक्त स्थान बनाते हैं। उन्होंने कहा कि सौर तथा पवन ऊर्जा उत्पादन को एकीकृत करने की दिशा में पहल करते हुए पश्चिमी राजस्थान में एक ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इसमें एक ग्रिड सब स्टेशन का नेटवर्क भी शामिल है, जिससे 6311 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पादित होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नवीकरणीय ऊर्जा की उत्पादक कंपनियों को उचित दरों पर बड़े सरकारी भूखंड उपलब्ध करवा रही है। केंद्र एवं राज्य सरकार कौशल संवर्धन, बुनियादी ढांचा और तकनीकी विकास के लिए अनेक योजनाएं भी संचालित कर रही है।

शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2030 तक देश में 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया है जो उनके पंचामृत लक्ष्यों का एक अहम हिस्सा है। यह लक्ष्य भारत के ऊर्जा भविष्य को संवारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है तथा हमारे राष्ट्र की हरित ऊर्जा क्रांति का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में ही 4.5 गीगावाट के लक्ष्य के मुकाबले छह गीगावाट की ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है। वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री ने रखा है उसे हासिल करने में राजस्थान महत्वपूर्ण योगदान देगा। शर्मा ने कहा कि आज शुरू हुआ यह संयंत्र मेक इन इंडिया का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें भारत में बने हुए 100 प्रतिशत मॉड्यूल इस्तेमाल हुए हैं और 90 प्रतिशत कंपोनेंट की खरीद राजस्थान से की गई है। यह बात स्थानीय उद्योगों के लिए अच्छी है तथा आत्मनिर्भर भारत के हमारे विजन के भी अनुरूप है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशानुसार केन्द्र सरकार द्वारा लगातार ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप ऐसे संयंत्रों से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एनर्जी के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। इस दौरान शर्मा एवं जोशी ने सोलर प्लांट की लोकार्पण पट्टिका का अनावरण कर उद्घाटन किया।

## तीन बच्चों की हत्या कर मां-बाप ने की आत्महत्या की कोशिश

जोधपुर। संभाग के फलोदी क्षेत्र के कालू पाबूजी गांव में सोमवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक दंपति ने पहले अपने तीन बच्चों को ज़हर देकर बेहोश किया, फिर धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। इसके बाद पति-पत्नी ने खुदकुशी की भी कोशिश की, लेकिन समय रहते बचा लिया गया। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान 12 वर्षीय हरीश, 9 वर्षीय किरण और 2 साल की बच्ची नत्थू के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बच्चों को पहले कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई, फिर खाने में कीटनाशक मिला दिया गया। इसके बाद धारदार हथियार से बच्चों की गर्दन और हाथ की नसें काट दी गईं।

पुलिस पूछताछ में मां जतनो देवी ने बताया कि पति शिवलाल के साथ उसका अक्सर पैसों को लेकर विवाद होता था। घटना से कुछ दिन पहले ही शिवलाल ने अपनी सबसे छोटी बेटी नत्थू को ननिहाल से लाकर घर लाया था। इसके बाद ही उसने पूरे परिवार को खत्म करने की योजना बनाई। वारदात के बाद दोनों पति-पत्नी ने भी आत्महत्या का प्रयास किया, जिन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पड़ोस में रहने वाली गुड्डी नाम की महिला ने दी, जब स्कूल की वैन आने पर भी बच्चे घर से बाहर नहीं निकले। पुलिस को मौके से एक ब्लेड, चाकू और कीटनाशक की खाली शीशी बरामद हुई है। एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। मामले की जांच जारी है। गांव में इस घटना के बाद शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है।

# संस्कृत और संस्कृति के संरक्षण के लिए हो कार्य : बागड़े

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने संस्कृत को भाषा नहीं, भारत की महान संस्कृति और मानव संस्कारों की जननी बताते हुए कहा है कि संस्कृत और संस्कृति के संरक्षण के लिए काम करने तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा क्षेत्र में अच्छा मनुष्य बनाने के लिए कार्य किया जाना चाहिए। बागड़े जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के सप्तम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गुरु दक्षिणा के अंतर्गत शिक्षार्थियों को अपने विश्वविद्यालयों में पेड़ लगाने का कार्य किए जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे जहां विद्यार्थी पढ़े हैं, वहां से उनका सदा के लिए आत्मीय नाता बना रहेगा। उन्होने कहा कि संस्कृत और संस्कृति के संरक्षण के लिए सभी मिलकर कार्य करें।

उन्होंने भरतमुनि के नाट्यशास्त्र की चर्चा करते हुए कहा कि शिव का तांडव नृत्य और तमाम हमारा कला कौशल संस्कृत भाषा के जरिए ही जन जन तक पहुंचा है। राज्यपाल ने महर्षि आर्यभट्ट, भास्कराचार्य आदि की चर्चा करते हुए कहा कि भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को बहुत पहले ही प्रतिपादित कर बताया था कि गृह नक्षत्र और पृथ्वी में परस्पर आकर्षण रहता है। हर वस्तु पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण ज़मीन पर गिरती है। यह बल सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और नक्षत्रों को कक्षा में रहने की अनुमति देता है। उन्होंने संस्कृत ग्रंथों के जरिए भारतीय ज्ञान परम्परा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संस्कृत भाषा के प्रसार के साथ उसके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी रही है। बिरला ने कहा कि महापुरुषों ने भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा को संस्कृत भाषा में ही रचा। उन्होंने संस्कृत भाषा की प्राचीनता के साथ उसकी वैज्ञानिकता को आधुनिक दृष्टि देने के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय को कार्य करने का आह्वान किया। राज्य के संस्कृत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि संस्कृत विश्व की प्राचीन भाषाओं की सूत्रधार है। उन्होंने संस्कृत शिक्षा को आधुनिक ज्ञान विज्ञान का आधार बताया।

इससे पहले जूना अखाड़े के प्रमुख स्वामी अवधेशानंद गिरि ने सनातन भारतीय संस्कृति के प्राचीन ग्रंथों में निहित ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने विद्या वाचस्पति उपाधि प्रदान किए जाने पर विश्वविद्यालय का आभार जताया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रामसेवक दुबे ने विश्वविद्यालय द्वारा संस्कृत के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में प्रगति प्रतिवेदन पढ़ा। बागड़े एवं बिरला ने दीक्षांत समारोह में स्वामी अवधेशानंद गिरि को विद्यावाचस्पति की मानद उपाधि प्रदान कर उनका सम्मान किया। इससे पहले उन्होंने विश्वविद्यालय के न्यूज लेटर 'प्रवृत्ति:' के दीक्षांत समारोह विशेषांक का लोकार्पण भी किया।

# जयपुर में भी आएगी विभिन्न आय वर्ग के लिए आवासीय योजना

जयपुर/दक्षिण भारत । मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान आवासन मण्डल आम आदमी के आवास का सपना पूरा करने के लिए अविराम प्रयासरत है। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025-26 की क्रियान्विति में अप्रैल और मई माह में प्रदेश के विभिन्न जिलोंजयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, कोटा और हनुमानगढ़ में विभिन्न आय वर्गों के लिए नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत फ्लैट्स और स्वतंत्र आवास दोनों प्रकार के विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे ई डब्लू एस, एलआईजी, मध्यम आय वर्गों और उच्च आय वर्गों के परिवारों को किफायती, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसी के साथ ही अटरू, गजनपुरा,नैनवा , लाखेरी और धौलपुर में भी विभिन्न आवासीय योजना जल्द शुरू की जायेंगी। इसी के साथ ही जैसलमेर तथा नीमराना के करीब शाजहानपुर में भी मण्डल जल्द नवीन आवासीय योजना लाने की तैयारी कर रहा है। इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और विकास कार्यों में तेजी लाने को लेकर गुरुवार को आवास भवन में आवासन आयुक्त डॉ रश्मि शर्मा ने अहम बैठक ली।

डॉ. शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की मंसानुरूप आवासन मण्डल आम जन के आवास के सपने को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने अभियंताओं एवं अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन नवीन योजनाओं से संबंधित सभी कार्यों को सर्वोच प्राथमिकता के साथ पूरा करें साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि इनके निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। डॉ. शर्मा ने कहा कि चाहे ई नीलामी हो या आवासीय योजना, सैंकड़ों आवेदन और नीलामी द्वारा अर्जित करोड़ों का राजस्व इस बात का प्रमाण है कि आज भी आवासन मण्डल संपत्तियों में निवेश एवं घर खरीदने के लिए लोगों की पहली पसंद है। हमे हरसंभव प्रयास करना है कि हम इस प्रथम पायदान पर बने रहें और भविष्य में भी मण्डल के प्रति लोगों के विश्वास और रुझान को कायम रख सकें।

# देवनानी और आरिफ ने वक्फ कानून सहित विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा

जयपुर/दक्षिण भारत । राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां ने गुरुवार को यहां वक्फ कानून सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। देवनानी ने खां के विधानसभा पहुंचने पर पुष्प गुच्छ भेंट कर एवं दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत एवं अभिवादन किया। उन्होंने खां को विधानसभा डायरी, कैलेण्डर और नवाचारों का एक वर्ष पुस्तक की प्रति भेंट की। इस दौरान बिहार और राजस्थान राज्यों के विभिन्न विषयों, वक्फ संशोधन विधेयक 2025, पुलिस से सम्बंधित पुराने समय से चले आ रहे ऐसे कानून जिन्हें स्वतन्त्र भारत में नये परिवेश में बदलाव किये

जाने की आवश्यकता है और दोनों राज्यों के विधानमण्डलों से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।

देवनानी ने खां को राजस्थान विधानसभा का भवन और सदन का अवलोकन कराया। देवनानी ने खां को बताया कि राजस्थान विधानसभा को वन नेशन-वन एप्लीकेशन नेवा के तहत पेपरलैस किये जाने के लिए सदन में प्रत्येक विधायक की सीट पर आइपैड लगाये गए है।

उन्होंने बताया कि सदन को गुलाबी नगर जयपुर की तर्ज पर गुलाबी रंग के नये कलेवर में तैयार किया गया है। खां ने विधानसभा के सदन और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान जैसी पहलों की सराहना करते हुए देवनानी को नवाचारों के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी।

# भारत 2029 तक तीन लाख करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों का निर्माण करेगा : राजनाथ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**नई दिल्ली/भाषा।** रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि इस साल भारत का रक्षा उत्पादन 1.60 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की उम्मीद है और 2029 तक तीन लाख करोड़ रुपए मूल्य के सैन्य उपकरणों के निर्माण का लक्ष्य है।

राजनाथ ने कहा कि भारत रक्षा उपकरणों के आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और एक रक्षा औद्योगिक परिवेशी तंत्र बनाएगा, जो न केवल देश की जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि रक्षा निर्यात की क्षमता को भी मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री ने 'द वीक' पत्रिका द्वारा आयोजित 'डिफेंस कॉन्क्लेव 2025 – फोर्स ऑफ द फ्यूचर' में अपने संबोधन में यह बात कही। उन्होंने कहा, ''वह दिन दूर नहीं जब भारत न केवल विकसित देश के रूप में उभरेगा, बल्कि हमारी सैन्य शक्ति भी विश्व में शीर्ष पर होगी। इस वर्ष रक्षा उत्पादन 1.60 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाना चाहिए, जबकि हमारा लक्ष्य वर्ष 2029 तक तीन लाख करोड़ रुपए मूल्य के रक्षा उपकरण तैयार करना है। रक्षा मंत्री ने कहा कि जहां भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमताएं राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता पर केंद्रित हैं, वहीं वे विनिर्माण को वैश्विक 'आपूर्ति बाधाओं' से भी बचा रही हैं। उन्होंने घोषणा की, '' हमारा रक्षा निर्यात इस वर्ष 30,000 करोड़ रुपए और वर्ष 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाना चाहिए। सिंह ने इस

बात पर जोर दिया कि भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता का उद्देश्य विवादों और संघर्षों को भड़काना नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की रक्षा क्षमताएं क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक विश्वसनीय प्रतिरोधक शक्ति की तरह हैं और शांति तभी संभव है जब भारत मजबूत बना रहे। सिंह ने अपने संबोधन में स्वदेशीकरण, नवाचार और वैश्विक नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर तथा भविष्य के लिए तैयार' भारत के लक्ष्य हेतु एक आकर्षक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया।

रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर रहा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय रक्षा परिवेशी तंत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भी अपनी स्थिति बना रहा है। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र का पुनरुद्धार और सुदृढ़ीकरण सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली और सबसे बड़ी चुनौती इस मानसिकता को बदलना है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए केवल आयात करेगा।

सिंह ने कहा, ''आज, जहां भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहा है, वहीं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को लचीला बनाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम न केवल देश के रक्षा उत्पादन को मजबूत कर रहा है, बल्कि इसमें वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को लचीला और सुदृढ़ बनाने की क्षमता भी है। सिंह ने युद्ध की बदलती हुई प्रकृति पर जोर देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में संघर्ष और युद्ध अधिक हिंसक और अप्रत्याशित होंगे तथा साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से नए युद्धक्षेत्र के रूप में उभर रहे हैं और इसके साथ ही, पूरी दुनिया में कथानक और धारणा का युद्ध भी लड़ा जा रहा है।

सिंह ने रक्षा क्षेत्र में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि 200 वर्ष से अधिक पुराने आयुध कारखानों का निगमीकरण एक साहसिक लेकिन आवश्यक कदम था। रक्षा मंत्री ने कहा, '' आज आयुध कारखाने अपने नए स्वरूप में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और लाभ कमाने वाली इकाइयां बन गए हैं। मेरा मानना है कि 200 वर्ष से भी अधिक पुराने ढांचे को बदलना इस सदी का बहुत बड़ा सुधार है।

# न्यायाधीश के घर से नकदी मिलने के मामले में प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज की गई : धनखड़

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**नई दिल्ली/भाषा।** उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के आवास से बड़े पैमाने पर नकदी की बरामदगी से जुड़े मामले में प्राथमिकी दर्ज न किए जाने पर बृहस्पतिवार को सवाल उठाया और कहा कि क्या कानून से परे एक श्रेणी को अभियोजन से छूट हासिल है।

धनखड़ ने कहा, अगर यह घटना उसके (आम आदमी के) घर पर हुई होती, तो इसकी (प्राथमिकी दर्ज किए जाने की) गति इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट सरीखी होती, लेकिन उक्त मामले में तो यह बैलगाड़ी जैसी भी नहीं है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्र जांच या पूछताछ के खिलाफ किसी तरह का सुरक्षा कवच नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी संस्था या व्यक्ति को पतन की ओर धकेलने का सबसे पुख्ता तरीका उसे जांच से सुरक्षा की पूर्ण गारंटी प्रदान करना है। उच्चतम न्यायालय ने 14 मार्च को होली की रात दिल्ली में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर लगी भीषण आग को बुझाने के दौरान वहां कथित तौर पर बड़े पैमाने पर नोटों की अधजली गड्डियां बरामद होने के मामले की आंतरिक जांच के आदेश दिए थे। इसके अलावा, न्यायमूर्ति वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से वापस इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेज दिया गया था। धनखड़ ने मामले की आंतरिक जांच के लिए गठित तीन न्यायाधीशों की समिति की कानूनी वैधता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि तीन न्यायाधीशों की समिति मामले की जांच कर रही है, लेकिन जांच कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र है, न्यायपालिका का नहीं।

उपराष्ट्रपति ने दावा किया कि समिति का गठन संविधान या कानून के किसी प्रावधान के तहत नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, और समिति क्या कर सकती है? समिति अधिक से अधिक सिफारिश कर सकती है। सिफारिश किससे? और किसलिए? धनखड़ ने कहा, न्यायाधीशों के लिए हमारे पास जिस तरह की व्यवस्था है, उसके तहत अंततः एकमात्र कार्रवाई (न्यायाधीश को हटाना) संसद द्वारा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि समिति की रिपोर्ट का स्वाभाविक रूप से कोई कानूनी आधार नहीं होगा। यहां राज्यसभा प्रशिक्षुओं के एक समूह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, एक महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। भले ही इस मामले के कारण शर्मिंदगी या असहजता का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अब समय आ गया है कि इससे पर्दा उठाया जाए।

# वक्फ पर विपक्ष बोला: उच्चतम न्यायालय से उम्मीद, भाजपा ने सात दिन के समय का स्वागत किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**नई दिल्ली/भाषा।** विपक्षी दलों ने वक्फ (संशोधन अधिनियम) पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों का स्वागत करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि इस विषय को लेकर देश की शीर्ष अदालत से उम्मीद जगी है, क्योंकि यह नया कानून सिर्फ धार्मिक अधिकारों पर ही नहीं, बल्कि संविधान की मूल आत्मा पर हमला है।

दूसरी तरफ, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि विपक्षी दलों के याचिकर्ताओं ने अंतरिम आदेश के लिए दबाव बनाया, लेकिन शीर्ष अदालत ने सरकार को सात दिन का समय दिया, जो स्वागत योग्य कदम है।

उच्चतम न्यायालय ने पांच मई तक 'वक्फ बाय यूजर' समेत वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित नहीं करने और केंद्रीय वक्फ परिषद एवं वक्फ बोर्ड में नियुक्तियां न करने का केंद्र सरकार से आश्वासन लेने के साथ ही उसे संबंधित अधिनियम की वैधता पर जवाब दाखिल करने के लिए बृहस्पतिवार को सात दिन का समय दिया।

कांग्रेस नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने इस अधिनियम के माध्यम से किसी समुदाय नहीं, बल्कि संविधान की मूल आत्मा पर हमला किया है।

सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा, ''सरकार जिसे सुधार बता रही है, दरअसल वह अधिकारों पर प्रहार है। वक्फ अधिनियम प्रशासनिक कदम नहीं है, यह एक मूल वैचारिक हमला है। उन्होंने दावा किया, ''कानून सुधार की भाषा में यह अधिनियम पूरी तरह से शत-प्रतिशत नियंत्रण की नीति लाने का प्रयास करता है। यह न सिर्फ़ धार्मिक संस्थाओं पर चोट करता है, बल्कि अल्पसंख्यकों के आत्मनिर्णय, स्वायत्तता की भावना को कुचलता है। यह सत्ता की दखलंदाजी को सुशासन कहकर पेश करता है।

सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रहेगी और सड़क से लेकर संसद तक इस अधिनियम का विरोध करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ़ अधिनियम एक लक्षित अतिक्रमण है तथा यह अधिनियम प्रशासनिक कार्यकुशलता के नाम पर स्थापित न्यायिक सिद्धांतों को कुचलता है।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई कि उच्चतम न्यायालय मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों पर गंभीरता से विचार करेगा। उन्होंने 'पीटीआई वीडियो' से कहा, ''आज हमारी सबसे ज्यादा उम्मीद उच्चतम न्यायालय से है। जिस तरह की टिप्पणियां आईं हैं, उनको देखते हुए हमें उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों पर विचार करेगा।

# पूर्व मुख्यमंत्री हरेकृष्ण महताब के दृष्टिकोण ने ओडिशा को आकार दिया: गडकरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**कटक (ओडिशा)/भाषा।** केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री हरेकृष्ण महताब के दृष्टिकोण ने राज्य को आकार दिया।

गडकरी ने महताब की 125वीं जयंती के अवसर पर कटक स्थित रेवेनशॉ विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान 'बुनियादी ढांचे का विकास और ओडिशा' विषय पर एक व्याख्यान में यह बात कही।

एक स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि की तारीफ करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा, ''आप नेत्रदान कर सकते हैं, लेकिन दृष्टिकोण नहीं। महताब जी के दृष्टिकोण ने ओडिशा को आकार दिया है।

गडकरी ने कहा कि ओडिशा की पहचान और विकास में महताब का योगदान अद्वितीय है। उन्होंने हीराकुंड बांध के निर्माण में महताब के योगदान का भी जिक्र किया। दरअसल, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1948 में इसकी आधारशिला रखी थी और 1957 में इसका उद्घाटन किया गया था।

गडकरी ने महताब को बहुमुखी व्यक्तित्व का धनी बताते हुए कहा कि वह एक विद्वान, लेखक, कवि और समाज सुधारक थे, जिन्होंने राज्य में शैक्षिक उन्नति और सामाजिक समानता के लिए काम किया था।

महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले गडकरी ने बताया कि महताब ने पश्चिमी राज्य में कारावास के दौरान 'ओडिशा का इतिहास' नामक किताब लिखी थी। उन्होंने युवाओं से महताब के जीवन से प्रेरणा लेने का आग्रह करते हुए कहा, ''यह मायने नहीं रखता कि हम कितने लंबे समय तक जीवित रहते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि हम क्या करते हैं। आइए ओडिशा को भारत के विकास का अग्रणी केंद्र बनाने के लिए काम करें।

इससे पहले, गडकरी ने ओडिशा में 19 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का अनावरण किया, जिसमें 4,137 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उन्होंने भुवनेश्वर के बारामुंडा मैदान में आयोजित एक समारोह में 17 परियोजनाओं की आधारशिला रखी और दो राजमार्गों के खंडों का उद्घाटन किया।

इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उपमुख्यमंत्री पी. परिदा और केवी सिंह देव, सांसद, विधायक और मंत्री उपस्थित थे।

गडकरी ने 2,905 करोड़ रुपए की लागत वाली 13 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं के तहत खुर्दा, पुरी, गंजम, कंधमाल और नयागढ़ जिलों में नई सड़कें बनाई जाएंगी और मौजूदा सड़कों को चौड़ा किया जाएगा।

# बंगाल : भाजपा नेता घोष ने हिंदुओं से सुरक्षा के लिए हथियार रखने का आह्वान कर विवाद खड़ा किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**कोलकाता/भाषा।** पश्चिम बंगाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष द्वारा कथित तौर पर हिंदुओं से सुरक्षा के लिए घर में हथियार रखने की अपील के बाद विवाद खड़ा हो गया है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इस बयान की तीखी आलोचना करते हुए इसे ''भड़काऊ'' करार दिया है।

घोष को एक वीडियो में यह अपील करते सुना जा सकता है।

भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के पूर्व अध्यक्ष घोष ने उत्तर 24 परगना जिले में एक सार्वजनिक रैली में हाल ही में मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा, ''हिंदू टीवी, रेफ्रिजरेटर और नया फर्नीचर खरीद रहे हैं। लेकिन उनके घर में एक भी हथियार नहीं है। जब कुछ होता है तो वे पुलिस को बुलाते रहते हैं। पुलिस आपको नहीं बचाएगी। उन्होंने कहा, ''दस साल पहले लोग नहीं जानते थे कि रामनवमी जुलूस क्या होता है। आज हर इलाके में ऐसे जुलूस निकाले जा रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं को एहसास हो गया है कि उन्हें एकजुट होने की जरूरत है। यहां तक कि भगवान भी कमजोरों के साथ नहीं खड़े होते।

उनकी कथित टिप्पणियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि, 'पीटीआई-भाषा' स्वतंत्र रूप से वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सका। घोष को उनकी टिप्पणियों के लिए कई बार फोन किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

इस बीच, घोष की कथित टिप्पणियों को लेकर मुर्शिदाबाद जिले के तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर ने भाजपा नेता पर सांप्रदायिक विवाद भड़काने का आरोप लगाया। कबीर ने आरोप लगाया, ''अगर एक व्यक्ति दूसरे पर हमला करता है, तो जवाबी कार्रवाई होगी। ये भाजपा नेता हिंदुओं को भड़काने और पश्चिम बंगाल की सद्भावना को बाधित करने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं।

पिछले दिनों वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध के दौरान मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा में कम से कम तीन लोग मारे गए और सैकड़ों लोगों को अपने घर छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ा।

जिले में केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है और इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं, जबकि हिंसा में कथित संलिप्तता के लिए 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

# बर्खास्त 'बेदाग' शिक्षकों का कार्यकाल बढ़ाने के न्यायालय के फैसले का स्वागत : ममता

**कोलकाता/भाषा।** पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय के उस आदेश का स्वागत किया जिसमें उन 'बेदाग' शिक्षकों की सेवाएं बढ़ा दी गई हैं जिन्हें भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं की वजह से बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि अब उन्हें राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय के उस फैसले से पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ी राहत मिली जिसके मुताबिक उन बर्खास्त किए गए शिक्षकों की सेवाएं बढ़ा दी गई हैं, जिन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जांच के दौरान बेदाग पाया था।

बनर्जी ने शीर्ष अदालत के फैसले के तुरंत बाद राज्य सचिवालय 'नबान्न' में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''अदालत ने दिसंबर तक का समय दिया है। यह फिलहाल राहत की बात है। हम उनके वेतन को लेकर चिंतित थे क्योंकि पहले के फैसले में वेतन वितरण पर रोक लगा दी गई थी। हम वैकल्पिक रास्ता तलाश रहे थे।

# बंगाल : बेरोजगार हुए 'बेदाग' शिक्षक न्यायालय के आदेश से असंतुष्ट

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**कोलकाता/भाषा।** बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की वजह से उच्चतम न्यायालय द्वारा बर्खास्त किये गए पश्चिम बंगाल के सरकार-संचालित एवं उसके वित्त-पोषित विद्यालयों के शिक्षकों ने शीर्ष अदालत की ओर से उनकी सेवा को अस्थायी रूप से विस्तारित किये जाने को 'अल्पकालिक राहत' करार देते हुए असंतोष जताया।

हालांकि, पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने उनसे चिंता न करने का आग्रह किया तथा चल रही कानूनी लड़ाई में राज्य सरकार की ओर से पूरा समर्थन करने के वादे को दोहराया। न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सीबीआई द्वारा बेदाग पाए गए बर्खास्त शिक्षकों की सेवाएं 31 दिसंबर तक बढ़ा दीं। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने राज्य सरकार की इस दलील पर विचार किया कि इन बर्खास्तगी से विभिन्न सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह आदेश राज्य सरकार की याचिका पर आया, जिसने तीन अप्रैल के फैसले के बाद अदालत का रुख किया था।

शीर्ष अदालत के फैसले में विभिन्न विद्यालयों में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार दिया गया और पूरी चयन प्रक्रिया को ''दूषित और दागदार'' करार दिया गया।

# ओडिशा के भद्रक में अज्ञात लोगों ने फेंके देसी बम, सात घायल

**भद्रक (ओडिशा)/भाषा।** ओडिशा के भद्रक जिले में बदमाशों द्वारा देसी बम फेंकने से तीन महिलाओं सहित कम से कम सात लोग घायल हो गए। यह घटना बुधवार देर रात तिहिडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कम्पाडा गांव में घटी। पुलिस ने बताया कि दो अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और सड़क किनारे बैठे कुछ लोगों पर देसी बम फेंककर भाग गए। सभी पीड़ितों को पहले सीएचसी ले जाया गया और बाद में भद्रक जिला मुख्यालय अस्पताल (डीएचएच) में स्थानांतरित कर दिया गया।

# ओलिव रिडले प्रजाति का कछुआ ओडिशा से चार साल में 3,600 किमी तैरकर महाराष्ट्र के तट पर पहुंचा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**केंद्रपाड़ा (ओडिशा)/भाषा।** ओडिशा तट पर स्थित गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य में करीब चार साल पहले ऑलिव रिडले प्रजाति के एक कछुए को टैग किया गया था, जो बंगाल की खाड़ी के जरिए लगभग 3,600 किलोमीटर तैरकर महाराष्ट्र के एक समुद्र तट पर देखा गया। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई) के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने यह जानकार दी।

वैज्ञानिक ने बताया कि 18 मार्च 2021 को टैग किया गया यह कछुआ महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक समुद्र तट पर पाया गया था, जहां यह अंडे देने के लिए पहुंचा था। जेडएसआई के वरिष्ठ वैज्ञानिक बासुदेव त्रिपाठी ने कहा कि यह पहला मामला है जिसमें वह कछुआ अंडे देने के लिए इतनी दूर गया जिसने पहले ओडिशा के तट पर अंडे दिए थे। त्रिपाठी ने कहा कि सामान्यतः, प्रवास व्यवहार का अध्ययन करने के लिए ओडिशा में जिन कछुओं को टैग किया जाता है वे इतनी लंबी दूरी तय नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, इससे पहले, श्रीलंका के उत्तरी तट से मछुआरों ने कुछ टैग किए गए कछुओं को बचाया था। हालांकि, पूर्वी राज्य में टैग किए गए कछुओं के श्रीलंका में अंडे देने का कोई इतिहास नहीं है।

प्रवासन चलन के बारे में त्रिपाठी ने कहा कि समुद्री कछुए आमतौर पर भोजन की तलाश और अंडे देने के स्थानों के बीच प्रवास करते हैं। उन्होंने कहा, नर और मादा कछुए प्रजनन क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं, तथा आमतौर पर उन समुद्र तटों पर लौट आते हैं जहां उनका जन्म हुआ था। वैज्ञानिक ने कहा, बंगाल की खाड़ी के किनारे ओलिव रिडले कछुओं के भोजन और प्रजनन स्थलों की पहचान करने और उनके प्रभावी संरक्षण की रणनीति बनाने की जरूरत है। त्रिपाठी ने कहा, चूंकि ओडिशा तट से एक टैग किया हुआ कछुआ पहली बार महाराष्ट्र के तट पर अंडे देने पहुंचा है, इसलिए इन भ्रमणशील समुद्री प्रजातियों के व्यवहार पर अधिक विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन का केन्द्र है। त्रिपाठी ने कहा, इस मादा कछुए ने महाराष्ट्र स्थित स्थल पर अंडे देने के लिए कम से कम 3,600 किलोमीटर की कठिन यात्रा की। उन्होंने कहा, पूर्व में टैग किए गए ऑलिव रिडले समुद्री कछुए गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य से एक महीने के भीतर लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा करके उत्तरी श्रीलंका के समुद्र तक पहुंच गए, लेकिन उन्होंने वहां अंडे नहीं दिए। ओडिशा वन विभाग ने 1999 में कछुओं को टैग करने का चलन शुरू

# उप्र में दलित असुरक्षित, अपराधी बेखौफ: राहुल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

**नई दिल्ली/भाषा।** कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक मूक-बधिर दलित बच्ची से कथित तौर पर दुष्कर्म की घटना को लेकर बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि राज्य में दलित और महिलाएं असुरक्षित हैं तथा अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि इस घटना में जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए।

रामपुर में मूक-बधिर दलित बच्ची से कथित तौर पर दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 11 वर्षीय पीड़ित बच्ची का मेरठ मेडिकल कॉलेज में उपचार किया जा रहा है। बच्ची मंगलवार शाम घर के बाहर से लापता हो गई थी और बुधवार सुबह एक किसान ने बच्ची को खेत में बेहोशी हालत में पाया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पोस्ट किया, ''उत्तर प्रदेश के रामपुर में 11 वर्षीय दलित बेटी के साथ हुई दरिंदगी और क्रूरता बेहद शर्मनाक और झकझोरने वाली है। उप्र में लगातार ऐसे अपराध साफ़ तौर पर साबित करते हैं कि भाजपा सरकार में दलित और विशेष रूप से बेटियां पूरी तरह असुरक्षित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह भाजपा की दलित और महिला विरोधी मानसिकता का ही नतीजा है कि अपराधी कानून व्यवस्था से बेखौफ हैं और पीड़ित लाचार हैं। राहुल ने सवाल किया कि आखिर कब तक उत्तर प्रदेश की बेटियां ऐसी दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी? उन्होंने कहा, ''प्रशासन से सीधी-सीधी मांग है, अपराधी पर कठोर कार्रवाई करे और, पीड़िता और उसके परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाए।

## सुविचार

**अंतिम सफलता के तीन तरीके हैं: पहला तरीका दयालु होना है। दूसरा तरीका दयालु होना है। तीसरा तरीका दयालु होना है।**

## दक्षिण भारत राष्ट्रमत

# मुनीर का प्रलाप

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने जम्मू-कश्मीर और हिंदू समाज के बारे में जो बयान दिया, वह उनकी संकुचित मानसिकता को दर्शाता है। उसमें कट्टरता और अज्ञान का अंश बहुत ज्यादा है। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन के एक समारोह में मुनीर ने 'भारतविरोध' और 'हिंदूविरोध' के नाम पर तालियां तो खूब बटोरीं, लेकिन उनके शब्दों में काफी विरोधाभास था। मुनीर पाकिस्तान के बनने को इस तरह पेश कर रहे हैं, गोया वह इतिहास की ऐसी महान घटना थी, जिससे मानवता का बहुत भला हो गया! वे पाकिस्तानियों से कह रहे हैं कि अपने बच्चों को देश के बनने की कहानियां जरूर सुनाएं, ताकि वे उसे भूलें नहीं। ऐसा लगता है कि खुद मुनीर अपने देश का सही इतिहास नहीं जानते। पाकिस्तान नफरत की बुनियाद पर बना एक कृत्रिम राष्ट्र है। यह अपनी असल पहचान को हमेशा नकारता रहता है। पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक लाखों लोग इसकी वजह से जान गंवा चुके हैं। अगर यह किसी दिव्य शक्ति की ओर से इतना बड़ा वरदान होता (जैसा कि मुनीर दावा करते हैं) तो इसकी वजह से मानवता लहूलुहान क्यों हुई? क्यों बलोचिस्तान में आज़ादी की जंग चल रही है? क्यों केपीके में धमाके हो रहे हैं? क्यों सिंध अलग होना चाहता है? अगर यह मानवता पर कोई महान उपकार था तो पूर्वी पाकिस्तान (मौजूदा बांग्लादेश) के लोग आपसे अलग क्यों हो गए? क्यों वहां लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी थी? अगर आसिम मुनीर को पाकिस्तान में इतनी अनूठी विशेषताएं नज़र आती हैं तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उनके देश को लोग छोड़-छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? आम जनता की तो बात ही न करें, पाक के पूर्व सेना प्रमुख इस देश में नहीं रहना चाहते। जनरल कयानी, राहील शरीफ, क़मर जावेद बाजवा विदेशों में ऐश कर रहे हैं। परवेज मुशर्रफ विदेश में रहते हुए परलोक सिधारे थे। मुनीर ने भी ब्रिटेन, यूएई, अमेरिका या कनाडा बसने का इंतजाम जरूर कर लिया होगा।

आसिम मुनीर के शब्दों से स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान एक ऐसा नासूर है, जिसने मानवता को सदैव पीड़ा दी है। अगर इसके हुक्मरान कुछ अक्ल से काम लेते तो यह पड़ोसी देश कई क्षेत्रों में उन्नति कर सकता था, लेकिन इसे नासूर बनाए रखने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना ने संभाल रखी है। मुनीर ने हिंदू समाज के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, उससे उनके देश में एकजुटता पैदा नहीं होगी, बल्कि नफरत ही बढ़ेगी। सिंध में लाखों हिंदू परिवार रहते हैं। कई हिंदू पाकिस्तानी सशस्त्र बलों में कार्यरत हैं। इस तरह मुनीर अपने ही लोगों का अपमान कर रहे हैं। वे जिस 'दो क़ौमी' नज़रिए की बात कर रहे हैं, उसे भारतीय सेना 16 दिसंबर, 1971 को ढाका में दफ़्न कर चुकी है। मुनीर इतिहास का अध्ययन करें, वर्ष 1947 से आगे बढ़ें। याद करें, ढाका में रमना रेस कोर्स का नज़ारा, जब आप ही की तरह बड़ी-बड़ी डींगें हांकने वाले लेफ्टिनेंट जनरल एएके नियाज़ी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया था। मुनीर को वह दिन याद रखने में कुछ कठिनाई हो सकती है, क्योंकि तब वे महज़ तीन साल के थे। अलबत्ता उन्हें कारगिल युद्ध जरूर याद होगा, जब भारतीय सेना ने सैकड़ों 'पाकिस्तानी घुसपैठियों' को ढेर किया था। आज मुनीर कह रहे हैं कि भारतीय सेना उन्हें न तो डरा सकती है और न ही हरा सकती है! मुनीर जम्मू-कश्मीर के बारे में वही प्रलाप कर रहे हैं, जो उनके पूर्ववर्ती करते थे। वे अलगाववादियों को भड़काने की कितनी ही कोशिशें कर लें, अब यह दाल गलने वाली नहीं है। जम्मू-कश्मीर शांति और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। मुनीर उसकी फिक्र न करें, बल्कि पीओके खाली करने की तैयारी करें। वह इलाका एक-न-एक दिन भारत के पास आना ही है। आसिम मुनीर ने यह साबित करने के लिए पूरा जोर लगा दिया कि हिंदू समाज से उनका कोई संबंध नहीं है। वे ऐसे दावों को बार-बार दोहराने के लिए स्वतंत्र हैं। पाकिस्तानी सेना के एक पूर्व कैप्टन (जो अब मशहूर लेखक हैं) भी चालीस साल पहले ऐसे दावे करते थे। उन्हें यह पट्टी पढ़ाई गई थी कि हम तो विदेश से यहां राज करने आए थे। एक दिन उन्होंने अपना डीएनए टेस्ट करवा लिया। पता चला कि उनके पूर्वज हिंदू थे। मुनीर के परिवार की जड़ें भारत के पंजाब से हैं। उन पूर्व कैप्टन का परिवार भी पंजाब से था! आस्था बदल जाने से पूर्वज नहीं बदलते।

## ट्वीटर टॉक

रणथंभौर गणेश मंदिर मार्ग में बाघ द्वारा किए गए हमले में एक मासूम बच्चे की निर्मम मृत्यु का समाचार हृदय विदारक एवं पीड़ादायक है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह दुःखद सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

**-दीया कुमारी**

ऐसा लगता है कि जनविरोधी मोदी सरकार ने मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने से इंकार कर दिया है। ये मनरेगा श्रमिकों के अधिकारों पर कुल्हाड़ी चलाना है। हाल ही में संयुक्त संसदीय समिति ने मनरेगा श्रमिकों की रोज़ाना मजदूरी को 400 करने की सिफारिश की थी।

**-अशोक गहलोत**

कांग्रेस का इतिहास जनता के पैसे की लूट का रहा है और जब उन पर कार्रवाई होने लगती है तो रोने धोने का ढोंग करने लग जाते है। कांग्रेस नेताओं ने अपराध नहीं किया है तो वे अपनी बात कोर्ट में रखे और जांच एजेंसियों को सहयोग करें।

**-मदन राठौड़**

## प्रेरक प्रसंग

# ईश्वर की सर्वव्यापकता

द्वापर युग की बात है। एक दिन भगवान श्रीकृष्ण, अपनी बहन द्रौपदी के साथ शाम की सैर कर रहे थे। द्रौपदी जी भगवान श्रीकृष्ण से बोली, 'भैया, मैंने तो सुना है कि आप हर जगह मौजूद रहते हैं। पर उस समय आप कहां थे, जब दुःशासन मेरा चीर हरण कर रहा था?' श्रीकृष्ण पहले मुस्कराए और फिर उत्तर दिया, 'बहन, जब दुःशासन तुम्हारा चीर हरण कर रहा था, तब तुम अपनी साड़ी को दोनों हाथों से पकड़कर बचने का स्वयं प्रयास कर रही थी। थोड़ी देर के प्रयासों के बाद जब तुम्हारा जोर नहीं चला, तो तुमने सोचा यहां सभा में मेरे पांच पति बैठे हैं, वह मेरी मदद अवश्य ही करेंगे। जब वे लोग भी कुछ न कर सके और उदासीनता से बैठे रहे। तब तुमने सोचा कि इस सभा में एक से बढ़कर एक शूरवीर हैं, ये लोग मेरी मदद करेंगे। जब वहां से भी तुम्हें निराशा हाथ लगी, तो तुमने अंत में दोनों हाथ उठाकर कहा, 'हे ईश्वर मेरी इज़्ज़त की रक्षा कीजिए। तब मुझे तुम्हारी लाज बचाने के लिए आना पड़ा और अन्ततः दुःशासन को थक कर बैठ जाना पड़ा। इस तरह कौरव अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए।' मैं तो हर जगह उपस्थित रहता हूं, पर मनुष्य मुझे पुकारता ही सबसे अंत में है।

## सामयिक

# नई विश्व संरचना में विरासत एवं विकास का समन्वय अपेक्षित

**ललित गर्ग**
**मोबाइल : 9811051133**

विश्व धरोहर दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस मानव सभ्यता के इतिहास और विरासत को एक साथ सम्मान देने एवं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षित करने के लिए हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक परिदृश्यों और संरचनाओं का जश्न मनाना और उन पर ध्यान आकर्षित करना है, जो व्यक्तियों, समुदायों और राष्ट्रों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को की पहल पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई जो विश्व के सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। यह संधि सन 1972 में लागू की गई। प्रारंभ में मुख्यतः तीन श्रेणियों में धरोहर स्थलों को शामिल किया गया। पहले वह धरोहर स्थल जो प्राकृतिक रूप से संबद्ध हो अर्थात प्राकृतिक धरोहर स्थल, दूसरे सांस्कृतिक धरोहर स्थल और तीसरे मिश्रित धरोहर स्थल। वर्ष 1982 में इकोमार्क नामक संस्था के ट्यूनिशिया में अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस में यह बात उठी कि विश्व भर में विरासत दिवस का आयोजन किया जाना चाहिए। यूनेस्को के महासम्मेलन में इसके अनुमोदन के पश्चात विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा की गई। हर साल धरोहर दिवस की एक खास थीम होती है। साल 2024 में विश्व विरासत दिवस की थीम विविधता की खोज और अनुभव थी। वहीं इस साल थीम है आपदाओं और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासतः आईसीओएमएस की 60 वर्षों की कार्रवाइयों से तैयारी और सीख। यह थीम गौरवशाली अतीत में विश्व संस्कृतियों की सुंदरता को बढ़ाने एवं संरक्षित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

दुनिया के तमाम देशों में कई सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरें हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत घोषित किया है। इनमें से आठ ऐसी विश्व धरोहर हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय हैं। जिनमें मिस्र में मौजूद गीज़ा का 'ग्रेट पिरामिड' आज भी रहस्य बना हुआ है। 481 फीट ऊंचा यह पिरामिड विश्व के आठ प्राचीन अजूबों में शामिल है और माना जाता है कि इसे चांद से भी देखा जा सकता है। माचू पिच्चू, पेरू यह ऐतिहासिक स्थल पेरू की पहाड़ियों पर बसा है और रहस्यमयी और खूबसूरत माचू पिच्चू को 'इंकाओं का खोया हुआ शहर' भी कहा जाता है। चीन की महान दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, जिसकी लंबाई करीब 21,196 किलोमीटर है। यह दीवार कई राजाओं और साम्राज्यों द्वारा रक्षा के लिए बनाई गई थी। आगरा का ताजमहल मोहब्बत एवं प्रेम की सबसे खूबसूरत मिसाल है। इसे शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। यह सफेद संगमरमर की इमारत भारत की सबसे मशहूर धरोहरों में से एक है। क्राइस्ट द रिडीमर, ब्राजील रियो डी जेनेरियो में स्थित यीशु की यह विशाल प्रतिमा 30 मीटर ऊंची है। यह प्रतिमा न सिर्फ धार्मिक प्रतीक है, बल्कि शहर का प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। पेट्रा, जॉर्डन रेगिस्तान के बीच स्थित पेट्रा शहर अपनी अनोखी लाल पत्थर की इमारतों और मंदिरों के लिए जाना जाता है। इसकी वास्तुकला और नक्काशी पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। कोलोसियम, रोम (इटली) प्राचीन रोम के सम्राटों द्वारा बनवाया गया यह विशाल अखाड़ा कभी ग्लैडिएटरों की लड़ाई का गवाह था। यह आज भी रोम की पहचान बना हुआ है और विश्व धरोहर सूची में शामिल है। चिचेन इट्जा, मेक्सिको यह माया सभ्यता का प्रमुख धार्मिक स्थल रहा है। यहां बना 'एल कैस्टिलो' पिरामिड देखने लायक है। चिचेन इट्जा को मेक्सिको का सबसे संरक्षित पुरातात्विक स्थल माना जाता है।

**राजस्थान भारत का एक राज्य है जो विश्व विरासत का समृद्ध केन्द्र है, यह पर्यटन के लिए सबसे समृद्ध राज्य माना जाता है। राजस्थान की पुरातात्विक विरासत या सांस्कृतिक धरोहर केवल दार्शनिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थल के लिए नहीं है बल्कि यह राजस्व प्राप्ति का भी स्रोत है। यूं तो भारत के सभी राज्यों में समृद्ध विरासत देखने को मिलती है।**

भारत में ऐतिहासिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों से समृद्ध है। भारत में 43 यूनेस्को आधारित विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें से 35 सांस्कृतिक हैं, सात प्राकृतिक हैं और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान एक मिश्रित स्थल है। 62 अन्य संभावित सूची में हैं, यहाँ ऐतिहासिक स्थलों का खजाना है जो इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। 2024 में, असम से चराइदेव मोइदम विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली नवीनतम भारतीय प्रविष्टि बन गई। अहोम राजघरानों के दफ़न टीलों में गुंबददार कक्ष हैं, जो अक्सर दो-मंजिला होते हैं और जहां मेहराबदार मार्गों से पहुँचा जा सकता है। इन कक्षों में, मृतक को उनके सामान, जिसमें कपड़े और आभूषण, हथियार, फर्नीचर और दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुओं के साथ सुरक्षित रखा गया है।

विश्व विरासत दिवस सिर्फ हमारे जीवन में खुशियों के पलों को लाने में ही मदद नहीं करता बल्कि यह देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का माध्यम भी है। यह पर्यटन को प्रोत्साहन देने का सशक्त माध्यम है। भारत की अर्थव्यवस्था पर्यटन-उद्योग के इर्द-गिर्द घूमती रही है। भारत की विरासत विश्व में सबसे प्राचीन और समृद्ध विरासतों में से एक मानी जाती है। हज़ारों वर्षों से यह भूमि सांस्कृतिक, धार्मिक, प्राकृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अनेक महान परिवर्तनों एवं प्रगतियों की साक्षी रही है। भारतीय संस्कृति का इतिहास अत्यंत विविधतापूर्ण और बहुआयामी है, जिसने न केवल भारत बल्कि समग्र मानवता को गहराई से प्रभावित किया है। भारत की विकास यात्रा का इतिहास रोमांचक और प्रेरणादायक रहा है। स्वतंत्रता के बाद देश को एक ऐसे रास्ते पर चलना था जहाँ उसे पुनर्निर्माण के साथ-साथ आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाना था। वर्तमान में भारत विश्व की प्रमुख आर्थिक एवं प्रौद्योगिकीय शक्तियों में से एक है, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। स्वतंत्रता के बाद भारत को न केवल अपने सामाजिक और आर्थिक ढाँचे को पुनर्स्थापित करना था, बल्कि उसे एक ऐसे लोकतांत्रिक देश का निर्माण करना था जो अपने नागरिकों को समान अवसर और अधिकार प्रदान कर सके। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की थीम 'स्वर्णिम भारत- विकास के साथ विरासत' है। यह थीम देश की विरासत को संभालते हुए भारत की प्रगति की यात्रा को दर्शाती है। भारत अपनी सुंदरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है।

राजस्थान भारत का एक राज्य है जो विश्व विरासत का समृद्ध केन्द्र है, यह पर्यटन के लिए सबसे समृद्ध राज्य माना जाता है। राजस्थान की पुरातात्विक विरासत या सांस्कृतिक धरोहर केवल दार्शनिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थल के लिए नहीं है बल्कि यह राजस्व प्राप्ति का भी स्रोत है। यूं तो भारत के सभी राज्यों में समृद्ध विरासत देखने को मिलती है। पर्यटन क्षेत्रों से कई लोगों की रोजी-रोटी भी जुड़ी है। प्राकृतिक सुंदरता और महान इतिहास से संपन्न राजस्थान में पर्यटन उद्योग समृद्धिशाली है। राजस्थान देशीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों, दोनों के लिए एक सर्वाधिक आकर्षक पर्यटन स्थल है। भारत की सैर करने वाला हर तीसरा विदेशी सैलानी राजस्थान देखने ज़रूर आता है। जयपुर के महल, उदयपुर की झीलें और जोधपुर, बीकानेर तथा जैसलमेर के भव्य दुर्ग भारतीय और विदेशी सैलानियों के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक हैं। इन प्रसिद्ध विरासत स्थलों को देखने के लिए यहाँ हज़ारों पर्यटक आते हैं। जयपुर का हवामहल, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के धोरे काफी प्रसिद्ध हैं। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग, सवाई माधोपुर का रणथम्भोर दुर्ग एवं चित्तौड़गढ़ दुर्ग काफी प्रसिद्ध है। यहाँ शेखावटी की कई पुरानी हवेलियाँ भी हैं जो वर्तमान में हैरीटेज होटलें बन चुकी हैं।

विश्व विरासत दिवस केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं है, बल्कि चिंतन, कार्रवाई और प्रतिबद्धता का दिन है। इस अवसर का उपयोग सभी के लाभ के लिए अपने सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक संरक्षण में योगदान देना है। यह वैश्विक आयोजन सांस्कृतिक धरोहर के प्रति चिंतन करता है और इन अमूल्य खजानों के साथ जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन सांस्कृतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित और सुरक्षित रखने के महत्व को पहचानने, दुनिया भर में उनकी सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक महत्व के लिए सराहना को बढ़ावा देने का अवसर है।

## नजरिया

# देश में समाप्त होने के कगार पर पहुंचा नक्सलवाद

**रमेश सर्राफ धमोरा**
**मोबाइल : 9414255034**

पिछले छः दशकों से देश में नासूर बनकर उभरा नक्सलवाद अब समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। देश के गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में घोषणा की है कि 31 मार्च 2026 तक देश में नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। गृह मंत्री द्वारा की गई यह एक बहुत बड़ी घोषणा है। गत 60 वर्षों से देश नक्सलवाद की समस्या से बुरी तरह पीड़ित रहा है। इस दौरान देश में कई सरकारें आई और चली गई मगर नक्सलवाद का नासूर दिनों-दिन बढ़ता ही रहा था। देश के कई प्रदेशों में तो बहुत बड़े हिस्से में नक्सलवादी अपनी समानांतर सरकार तक चलाते थे। नक्सलवाद प्रभावित जिलों में उनकी हुकूमत चलती थी। वहां केंद्र व राज्य सरकार का कोई असर नहीं दिखता था। नक्सलियों का फरमान ही अंतिम आदेश होता था जिसे लोग मानने को मजबूर थे। मगर अब परिस्थितियों पूरी तरह बदल चुकी है। केंद्र सरकार की नक्सलवाद से मुक्ति के अभियान की सफलता से नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसे गिन रहा है। कई बड़े-बड़े नक्सली कमांडर सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं या फिर उन्होंने सरेंडर कर अपनी जान बचा ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनो कहा कि नक्सलवाद मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत ने वामपंथी उग्रवाद से अति प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटाकर 6 कर दिया है। शाह ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मोदी सरकार के दृष्टिकोण पर रोशनी डालते हुए और सभी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा था कि मोदी सरकार सर्वव्यापी विकास के लिए अथक प्रयासों और नक्सलवाद के खिलाफ दृढ़ रुख के साथ सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की कुल संख्या पहले 38 थी। इनमें से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या अब घटकर 6 हो गई है। साथ ही चिंता के जिलों और अन्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या में भी कमी आई है। नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित छह जिलों में अब छत्तीसगढ़ में चार जिले बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम जिला व महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला शामिल है। इसके अतिरिक्त चिंता के जिलों की संख्या जिन्हें गहन संसाधनों और ध्यान की आवश्यकता है 9 से घटकर 6 रह गई है। ये जिले आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू, मध्य प्रदेश में बालाघाट, ओडिशा में कालाहांडी, कंधमाल और मलकानगिरी और तेलंगाना में भद्राद्री-कोठागुडेम हैं।

अन्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या जो नक्सली गतिविधि का भी सामना कर रहे हैं लेकिन कम हद तक 17 से घटकर 6 हो गई है। इनमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, गरियाबंद और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चैकी, झारखंड का लातेहार, ओडिशा का नुआपाड़ा और तेलंगाना का मुलुगु जिला शामिल हैं। इन जिलों को उनके पुनर्निर्माण और विकास में सहायता करने के लिए केंद्र सरकार विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सबसे अधिक प्रभावित जिलों को 30 करोड़ रुपये मिलते हैं। जबकि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में अंतराल को भरने के लिए चिंता वाले जिलों को 10 करोड़ रुपये आवंटित किए जाते हैं। इन क्षेत्रों की जरूरतों के अनुरूप विशेष परियोजनाओं को भी सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते वर्ष 2025 में अब तक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ों में कम से कम 130 नक्सली मारे गए हैं। इनमें से 110 से ज्यादा बस्तर संभाग में मारे गए जिसमें बीजापुर और कांकेर समेत सात जिले शामिल हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से 105 से अधिक नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 2025 में अब तक 164 ने आत्मसमर्पण कर दिया है। वहीं इससे पहले वर्ष 2024 में 290 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया था 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया था। अभी तक कुल 15 शीर्ष नक्सली नेताओं को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है।

वर्ष 2014 तक कुल 66 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन थे जबकि मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में इनकी संख्या बढ़कर 612 हो गई है। इसी प्रकार, 2014 में देश में 126 जिले नक्सलप्रभावित थे लेकिन 2024 में सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या घटकर मात्र 12 रह गई है। पिछले 5 वर्षों में कुल 302 नए सुरक्षा कैंप और 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड्स बनाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2004 से 2014 तक देश में नक्सलवाद से जुड़ी 16,463 हिंसक घटनाएं हुई थीं। लेकिन पिछले 10 वर्षों में इसमें 53 प्रतिशत कमी आई है।

वर्ष 2004 से 2014 तक विभिन्न नक्सली हमलों और नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान 1851 सुरक्षा कर्मियों की जान गई थी। लेकिन पिछले 10 साल में सुरक्षाबलों के हताहत होने की संख्या 73 प्रतिशत घटकर 509 रह गई है। वहीं 2004 से 14 के बीच नक्सली हमलों में 4,766 नागरिकों की मौत हुई थी। 2014 से 2024 के बीच यह आंकड़ा 70 प्रतिशत घटकर 1495 रह गया है। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में अब तक 90 नक्सली मारे जा चुके हैं, 104 को गिरफ्तार किया गया है और 164 ने आत्मसमर्पण किया है। वर्ष 2024 में 290 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया था, 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया था। पिछले 20 वर्षों में 2,344 सुरक्षाकर्मियों ने नक्सलियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई है पिछले दो दशकों में अकेले नक्सली हमलों में 6,258 लोग मारे गए हैं। जब देश में नक्सलवाद अपने चरम पर था तब 8 करोड़ लोगों को प्रभावित किया था। जिनमें मुख्य रूप से आदिवासी थे। यह आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में फैले एक लाल गलियारे के साथ 10 राज्यों में फैला हुआ था।

सरकार एक तरफ जहां नक्सलवाद को समाप्त करने की घोषणा कर रही है वहीं दूसरी तरफ शहरी नक्सलवाद जिसे अर्बन नक्सलवाद भी कहा जाता है तेजी से उभर रहा है। यह पारंपरिक ग्रामीण नक्सलवाद से अलग है क्योंकि इसका फोकस शहरों और शहरी इलाकों में होता है। शहरी नक्सली विचारधारा के समर्थक, जिनमें शिक्षाविद, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल होते हैं नक्सलवादी विचारधारा का प्रचार-प्रसार करते हैं। वे विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक माध्यमों से अपनी विचारधारा फैलाते हैं और व्यवस्था के खिलाफ असंतोष को भड़काते हैं। देश में नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार के समग्र प्रयासों का असर दिखने लगा है। सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि अब देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में कमी हो रही है। सरकार ने नक्सलवाद-मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।

देश में वामपंथी उग्रवाद से अति प्रभावित जिलों की संख्या में कमी आना इस आंदोलन की समाप्ति के संकेत है। नक्सलवादी आंदोलनकारियों ने अपनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हजारों निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों ने भी नक्सलवादी विरोधी अभियान में अपनी शहादत दी है। एक समय था जब देश के 10 प्रांतो में नक्सलवादियों की तूती बोलती थी। इन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर भी हमला कर दिया था। जगदलपुर में तो नक्सलवादियों ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की हत्या कर सनसनी फैला दी थी। मगर अब केंद्र सरकार की नीतियों के कारण एक तरफ जहां इन पर दबाव बढ़ा है वहीं उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में सरकार ने विकास की योजनाएं प्रारंभ कर उनका जन समर्थन समाप्त कर दिया है। कई बड़े नक्सली कमांडरो का एनकाउंटर होने के बाद डर कर बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। जिससे आने वाले समय में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शांति व्याप्त होगी। जो सरकार व आमजन की एक बड़ी जीत होगी।

महत्त्वपूर्ण
Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law. **Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।– दक्षिण भारत राष्ट्रमत

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा असम के कार्बी आंगलोंग की सुंदर पहाड़ियों की अपनी यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए।

# भारत को पाकिस्तान से घनिष्ठ संबंध बनाने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए : हिमंत

गुवाहाटी/भाषा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की हालिया टिप्पणियों पर बृहस्पतिवार को कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि भारत सच्चाई को स्वीकार करे और पाकिस्तान से घनिष्ठ संबंध बनाने की उम्मीद छोड़ दे।

शर्मा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ''अपने हालिया संबोधन में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने साफ कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच गहरी वैचारिक खाई है।

मुनीर का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत और पाकिस्तान मूल रूप से अलग देश हैं, क्योंकि दोनों देशों के धर्म, रीति-रिवाज, परंपराएं, सोच और महत्वाकांक्षाएं हर पहलू में एक-दूसरे से अलग हैं।

शर्मा ने कहा, ''यह परिप्रेक्ष्य द्वि-राष्ट्र सिद्धांत को पुष्ट करता है, जिसने 1947 में पाकिस्तान के निर्माण की नींव रखी।

मुख्यमंत्री ने कहा, ''अब यह साफ हो चुका है कि हमारे रास्ते अलग हैं। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र को मजबूत करें, अपने धर्म और सभ्यतागत मूल्यों को बनाए रखें। ऐसा करके ही हम अपने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं।

जनरल मुनीर ने विदेश में रह रहे पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र हैं। उन्होंने कहा था, ''हम एक राष्ट्र नहीं हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इस देश को बनाने के लिए संघर्ष किया। हमारे पूर्वजों और हमने इस देश के निर्माण के लिए बहुत त्याग किया है। हम जानते हैं कि इसकी रक्षा कैसे करनी है।

## 'ग्राउंड रिपोर्ट' में भावना नहीं, सच्चाई दिखाना था मकसदः इमरान हाशमी

मुंबई/भाषा। अभिनेता इमरान हाशमी का कहना है कि उनकी आने वाली फिल्म 'ग्राउंड ज़ीरो' का उद्देश्य देशभक्ति को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना नहीं, बल्कि एक सच्ची कहानी को ईमानदारी से पेश करना है जिसका असली नायक एक बीएसएफ अधिकारी है।

फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी की एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकारी नरेंद्र नाथ धर दुबे की वीरगाथा दिखाई गई है, जिन्होंने वर्ष 2001 में संसद और अक्षरधाम मंदिर पर हुए आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए अभियान चलाया था।

इमरान हाशमी ने 'पीटीआई-भाषा' से बातचीत में कहा, शुरुआत से ही मेरी यही सोच थी कि फिल्म में देशभक्ति को बढ़ाचढ़ा कर नहीं दिखाना है, क्योंकि तब वो ज़बरदस्ती लगने लगता है। दर्शकों को तब कहानी से जुड़ाव नहीं होता। उन्होंने कहा कि फिल्म के निर्माण के दौरान उन्होंने सत्यता और ईमानदारी को सबसे पहले रखा। उन्होंने कहा, हमने इसमें ड्रामा और मनोरंजन तो रखा, लेकिन उस हद तक कि वह वर्ष 2001 की सच्ची घटना की सच्चाई को तोड़े नहीं। अगर ड्रामा ज़्यादा हो गया, तो बात बिगड़ जाती है।

हाशमी ने फिल्म में एक संवाद प्रहार होगा का ज़िक्र करते हुए कहा कि ड्रामे के साथ थोड़ी रचनात्मक स्वतंत्रता ज़रूरी होती है, लेकिन अगर वो देशभक्ति के नाम पर नकली लगे, तो बात बिगड़ जाती है।

इमरान हाशमी ने बताया कि उन्होंने खुद दुबे से मुलाकात की ताकि उनके किरदार की गहराई को समझ सकें। उन्होंने कहा, मैं कोई नक़ल नहीं करना चाहता था। जब आप बीएसएफ की दुनिया को दर्शा रहे हों, तो आपको हर पहलू को सही ढंग से पेश करना होता है।

विरोध

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ को रांची में झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन द्वारा भारत के संविधान और इस्लामी शरीयत कानून के कार्यान्वयन पर की गई टिप्पणी के खिलाफ आक्रोश विरोध रैली के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होते हुए।

# मजाक नहीं : भेड़ों और अल्पाकाओं से अधिक बुद्धिमान साबित हुई हैं बकरियां

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

ऐबरिस्टविथ (ब्रिटेन)। जब हम बुद्धिमान पशुओं के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर भेड़-बकरी जैसे जानवर हमारे जेहन में सबसे पहले नहीं आते। हमारे जेहन में चिंपांजी, आरंगुटान, कैपुचिन्स जैसे पशु या कौए जैसा पक्षी आता है। लेकिन मेरे शोध में पता चला है कि भेड़, बकरियां और अल्पाका जैसे पशु भी कम अक्लमंद नहीं होते।

दो अलग-अलग अध्ययनों में, मैंने पता लगाया कि ये जानवर कैसे सीखते हैं, याद रखते हैं और अपने आस-पास की दुनिया को कैसे समझते हैं। निष्कर्षों से न केवल यह पता चलता है कि हमने उनकी सोचने-समझने क्षमताओं को कम करके आंका है, बल्कि जानकारी भी मिली कि इन पशुओं के बीच भी महत्वपूर्ण अंतर हैं।

तीनों पशुओं में से बकरियां शीर्ष पर रहीं और उन्होंने याददाश्त व समस्या के समाधान के मामले में भेड़ों और अल्पाकाओं दोनों से बेहतर प्रदर्शन किया।

प्रारंभिक अध्ययन भोजन जैसी किसी महत्वपूर्ण चीज के स्थान को याद रखने की क्षमता पर केंद्रित था। जंगल में, यह जीवित रहने का एक महत्वपूर्ण कौशल है। जानवरों को यह याद रखने की जरूरत होती है कि उन्हें पानी, भोजन या आश्रय कहां मिलेगा।

मैंने एक सरल प्रयोग किया। प्रत्येक जानवर को एक छोटे से क्षेत्र में कई बाल्टियों में से एक में छिपा हुआ भोजन ढूंढना था। एक बार जब उन्हें पता चल गया कि भोजन कहां है, तो मैंने उनकी जगह बदल दी और पता लगाया कि वे कितनी जल्दी और कितनी सटीकता से उसे ढूंढ सकते हैं।

आसपास की चीजों को लेकर बकरियों की याददाश्त सबसे तेज दिखी, वे भोजन को तेजी से ढूंढती हैं और दूसरों की तुलना में कम गलतियां करती हैं। भेड़ों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि उन्होंने बकरियों की तुलना में अधिक गलतियां कीं। अल्पाका को समय सीमा के अंदर कार्य पूरा करने में संघर्ष करना पड़ा।

बकरियों की यह याददाश्त उनके विकासवादी इतिहास से जुड़ी हो सकती है। वे विस्तृत, चट्टानी परिदृश्यों में चारा खोजने में अभ्यस्त होती हैं और उन्होंने संभवतः तेज याददाश्त विकसित की है जो चीजों को कुशलतापूर्वक खोजने और अच्छे भोजन के स्रोतों तक पहुंचने में उनकी मदद करती है।

दूसरे अध्ययन में सोचने-समझने के अधिक जटिल कौशलों पर ध्यान दिया गया, जिनमें वस्तु की जगह, किसी चीज की मात्रा को समझना और वर्गीकरण करना शामिल है। ये सभी बदलती दुनिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं।

उदाहरण के लिए, यदि आपने कभी किसी बच्चे के साथ लुका-छिपी खेल खेला हो, तो हो सकता है कि आपने बिना जाने ही वस्तु का स्थान पता लगा लिया हो।

इस कौशल से यह जानना होता है कि कोई वस्तु तब भी मौजूद है जब वह दृष्टि से छिपी हुई हो।

यह आसान लगता है, लेकिन यह क्षमता मनुष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण विकासात्मक उपलब्धि है। अन्य जानवर भोजन, शिकारियों, शिकार या अपने बच्चों का पता लगाने के लिए इस कौशल का उपयोग करते हैं। यह जीवित रहने के लिए एक आवश्यक कौशल है।

इसलिए, इस प्रयोग के लिए, मैंने एक कप के नीचे भोजन रखा और धीरे-धीरे गतिविधि को जटिल बना दिया। इसके बाद मैंने खाली कप रखे, या कपों की जगह बदल दी ताकि पशु को छिपे हुए भोजन को खोजना पड़े।

बकरियों ने इस कार्य में भी उत्कृष्टता दिखाई। उन्होंने भेड़ों और अल्पाका की तुलना में वस्तु की जगह के बारे में अधिक जागरूकता दिखाई, और इससे मानसिक रूप से यह पता लगाने की उनकी क्षमता प्रदर्शित की कि वस्तु कहां छिपी हुई है।

अन्य कार्यों में, भोजन की ज्यादा और कम मात्रा को लेकर तीनों पशुओं की समझ के बारे में पता चला, आमतौर पर उन्होंने अधिक भोजन वाले कंटेनर को चुना। लेकिन एक जैसे बर्तनों में भोजन रखकर पेश किया गया तो उन्हें कम या ज्यादा को चुनने में परेशानी हुई।

विरोध

डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) की राज्य सचिव मीनाक्षी मुखर्जी, ऑल बंगाल टीचर्स एसोसिएशन (एबीटीए) के सदस्यों, वामपंथी छात्र नेताओं, युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ गुरुवार को कोलकाता के साल्ट लेक में एसएससी भवन तक विरोध मार्च में भाग लेती हुई।

# पांच सितंबर को रिलीज होगी फिल्म 'दिल मधरासी'

**मुंबई/एजेन्सी**

दक्षिण भारतीय फिल्म स्टार शिवकार्तिकेयन की आने वाली फिल्म 'दिल मधरासी' पांच सितंबर को रिलीज होगी। शिवकार्तिकेयन पहली बार जाने-माने निर्देशक ए.आर. मुरुगदॉस की धमाकेदार एक्शन थ्रिलर 'दिल मदरासी' में काम करते नजर आयेंगे। अमरन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद शिवकार्तिकेयन अब मुरुगदॉस के साथ मिलकर फैंस को एक और सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। श्री लक्ष्मी मूवीज़ के बैनर तले बन रही 'दिल मधरासी' की रिलीज डेट का एलान कर दिया गया है, जिससे फैंस की एक्साइटमेंट और

भी बढ़ गई है। इस फिल्म की सिनेमैटोग्राफी की कमान सुदीप एलामोन ने संभाली है, जबकि म्यूजिक को अनिरुद्ध रविचंदर अपने धमाकेदार बैकग्राउंड स्कोर से और भी खास बनाने वाले हैं। ए.आर. मुरुगदॉस के निर्देशन में बन रही 'दिल मधरासी' में जबरदस्त स्टारकास्ट नजर आने वाली है। इस फिल्म में रुश्मिणी वसंथ, विद्युत जामवाल, बिजु मेनन, शब्बीर और विक्रांत जैसे दमदार कलाकार शामिल हैं। फिल्म की एडिटिंग श्रीकर प्रसाद ने की है और एक्शन कोरियोग्राफी केविन और धिलीप मास्टर्स ने संभाली है। 'दिल मधरासी' सिनेमाघरों में 05 सितंबर 2025 को रिलीज़ होगी।

# सनी देओल का ऐलान, 'नए मिशन के साथ आ रही है जाट 2'

**मुंबई/एजेन्सी**

10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई सनी देओल, रणदीप हुड्डा स्टारर 'जाट' बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ की कमाई कर चुकी है। सनी देओल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर प्रशंसकों को बताया कि 'जाट' के बाद अब 'जाट 2' नए मिशन के साथ आ रही है। अपकमिंग एक्शन फिल्म का निर्देशन भी गोपीचंद मलिनेनी करेंगे। वहीं, पोस्टर में निर्माता नवीन यरनेनी, रविशंकर वाई और टीजी विश्व प्रसाद के नाम भी उजागर किए गए हैं। 'जाट 2' का निर्माण भी मैत्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन हाउस करेगा। फिल्म के सीक्वल में सनी देओल की पुष्टि हुई है। हालांकि, अन्य कलाकारों के बारे में निर्माताओं ने जानकारी नहीं दी है। हालिया रिलीज फिल्म 'जाट' का निर्देशन गोपीचंद मलिनेनी ने किया है। सनी देओल के साथ फिल्म में रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार सिंह, सैयामी खेर और रेजिना कैसंड्रा भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म में अभिनेता रणदीप हुड्डा खतरनाक खलनायक 'रणतुंगा' के किरदार में हैं। फिल्म में उर्वशी रौतेला का एक आइटम सॉन्ग 'टच किया' भी है।

'जाट' में अपने किरदार को लेकर सनी देओल काफी उत्साहित रहे हैं। उन्होंने प्रचार के दौरान 'जाट' तक पहुंचने की यात्रा का जिक्र किया था। बताया, इस फिल्म की यात्रा 'गदर 2' के दौरान शुरू हुई थी। हम सभी इसे लेकर बहुत उत्साहित थे, हम एक खूबसूरत फिल्म शुरू करने वाले थे और कई निर्देशकों के साथ सलाह लेने के बाद गोपी फिल्म करने के लिए सहमत हो गए। हम गोवा में मिले और उन्होंने कहा कि वे फिल्म का निर्देशन करेंगे और इस तरह से हमने फिल्म पर काम किया। अभिनेता ने आगे बताया, गोवा में मुलाकात के दौरान गोपी ने कहा कि उनके पास सुनाने के लिए एक और कहानी है। उन्होंने मुझे सॉरी बोल-बोलकर पूरी फिल्म और कहानी में खींच लिया। इस तरह हमने 'जाट' बनाई। हिंदी के साथ ही तमिल और तेलुगू में रिलीज हुई फिल्म 'जाट' का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने पीपल मीडिया फैक्ट्री के साथ मिलकर किया है।

# 'वागले की दुनिया' में सुगंधा मिश्रा की हुई एंट्री

**मुंबई/एजेन्सी**

सोनी सब के शो वागले की दुनिया –नई पीढ़ी, नए किस्से में अभिनेत्री और कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा की एंट्री हो गयी है। सुगंधा मिश्रा ,'वागले की दुनिया' में सुमन गढिया का किरदार निभाती नजर आयेंगी। यह एक अल्हड़, बेहद नाटकीय और चालाक महिला है, जिसे हर परिस्थिति को ड्रामा में बदलने की कला बखूबी आती है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को एक चौंकाने वाला मोड़ देखने को मिलेगा, जब सुमन एक सुनियोजित जाल में राजेश वागले (सुमीत राघवन) को फंसाते हुए उन पर अनुचित व्यवहार का झूठा आरोप लगा देती हैं। सुगंधा मिश्रा ने कहा, मुझे सुमन का किरदार पहली ही बार में बेहद पसंद आ गया। वह अजीब, अप्रत्याशित और परतों से भरा है । एक ऐसा रोल जो आपको एक्टिंग का भरपूर आनंद देता है और खुद को बार-बार चौंकाने का मौका देता है। मेरे अंदर हमेशा से थोड़ा सा 'ड्रामा क्वीन' था, इसलिए सुमन का किरदार निभाना मेरे लिए काफी स्वाभाविक लगा। यह किरदार मजेदार तो है ही, पर पहली बार कुछ गंभीर और भावनात्मक दृश्य करने का मौका भी मिला, जो चुनौतीपूर्ण और रोमांचक दोनों रहा। भारती आचरेकर जी जैसे दिग्गज कलाकार के साथ स्क्रीन शेयर करना मेरे लिए सम्मान की बात थी डर भी लगा और प्रेरणा भी मिली।

पूरी टीम ने मुझे बहुत अपनापन दिया और पूरे सफर में बेहद सहयोगी और उत्साहवर्धक रही। सुमित राघवन ने कहा, राजेश एक ऐसा किरदार है जो हमेशा सही काम करने में विश्वास रखता है, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। इस वजह से उस पर इतना गंभीर आरोप लगना उसके लिए और पूरे परिवार के लिए एक बड़ा भावनात्मक झटका है। शो ने इस ट्रैक को बेहद संवेदनशीलता और खूबसूरती से प्रस्तुत किया है, जिसमें रिश्तों की ताकत और सच्चाई की अहमियत को भी उभारा गया है। सुगंधा के साथ काम करना

आनंददायक रहा। उन्होंने सेट पर नई ऊर्जा ला दी और सुमन के किरदार को पूरी तरह जीवंत कर दिया। पर्दे के पीछे हम खूब हंसे, लेकिन ऑन-स्क्रीन भावनात्मक दृश्यों में भी उन्होंने लाजवाब संतुलन दिखाया। वागले की दुनिया ,नई पीढ़ी, नए किस्से, सोमवार से शनिवार, रात 9 बजे, सिर्फ सोनी सब पर प्रसारित होता है।

# 'हॉन्टेड 3डी : घोस्ट्स ऑफ द पास्ट' फिर से डराने को तैयार

**मुंबई/एजेन्सी**

साल 2011 में रिलीज हुई हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड 3डी' की सफलता के बाद एक बार फिर से निर्माता-निर्देशक विक्रम भट्ट दर्शकों को हॉरर जोन में ले जाने के लिए तैयार है। 'हॉन्टेड 3डी: घोस्ट्स ऑफ द पास्ट' के जरिए मनोरंजन को तैयार विक्रम ने फिल्म निर्माता महेश भट्ट, आनंद पंडित के साथ हाथ मिलाया है। बहुप्रतीक्षित फिल्म 'हॉन्टेड 3डी: घोस्ट्स ऑफ द पास्ट' इसी साल 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म का फर्स्ट लुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। महेश भट्ट और आनंद पंडित द्वारा प्रस्तुत फिल्म के निर्देशक विक्रम भट्ट हैं। 'हॉन्टेड 3डी: घोस्ट्स ऑफ द पास्ट' में महाक्षय चक्रवर्ती और चेतना पांडे मुख्य भूमिकाओं में हैं। अपकमिंग हॉरर मिस्ट्री का निर्माण आनंद पंडित, राकेश जुनेजा और श्वेतांबरी भट्ट ने मिलकर किया है। घोषणा से पहले महाक्षय ने पहले ही संकेत दिया था कि सीक्वल पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा था कि 'हॉन्टेड 3डी' वापसी करेगी और विक्रम भट्ट एक बार फिर निर्देशक की भूमिका निभाएंगे।

निर्माताओं के अनुसार बहुप्रतीक्षित सीक्वल फिल्म का टीजर रेडी है और जल्द ही जारी किया जाएगा। 'हॉन्टेड 3डी' की बात करें तो साल 2011 में रिलीज हुई यह फिल्म भट्ट कैंप की सबसे बेहतरीन हॉरर फिल्मों में से एक है। फिल्म विक्रम भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म में मिमोह, टिया बाजपेयी, अचिंत कौर और आरिफ जकारिया मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे युवक पर केंद्रित है, जो एक लड़की की आत्मा से खुद को जुड़ा पाता है। जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, परत दर परत रहस्य की गुत्थी सुलझती चली जाती है। उसे पता चलता है कि लड़की को उसके पियानो शिक्षक ने प्रताड़ित किया था। 2023 में रिलीज हुई '1920: हॉरर्स ऑफ द हार्ट' का निर्देशन कृष्णा भट्ट ने किया है और इसका निर्माण विक्रम भट्ट ने किया है। यह 1920 फिल्म सीरीज की पांचवीं फिल्म थी। इसमें अविका गौर और राहुल देव मुख्य भूमिका में थे। बरखा बिष्ट, रणधीर राय, दानिश पंडोर, केतकी कुलकर्णी, अवतार गिल और अमित बहल सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे।

# संगीत में एआई का संभावित दुरुपयोग ऑक्सीजन में जहर घोलने जैसा : रहमान

मुंबई/भाषा। ऑस्कर पुरस्कार विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान का कहना है कि संगीत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के इस्तेमाल के अच्छे और बुरे दोनों पहलू हैं, लेकिन अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो अराजकता फैल जाएगी। उन्होंने कहा कि वह संगीत में नई तकनीक के इस्तेमाल के खिलाफ नहीं हैं और वास्तव में उन्होंने रजनीकांत अभिनीत फिल्म लाल सलाम के एक गीत 'थिमिरी येझुदा' के लिए दिवंगत गायकों बंबा बाक्या और शाहुल हमीद की आवाज के लिए एक एआई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया। रहमान ने कहा कि लेकिन उन्होंने संगीतकारों के परिवार से उचित अनुमति लेकर ऐसा किया।

रहमान ने स्वीकार किया कि संगीत में एआई का उपयोग बेतहाशा बढ़ गया है। उन्होंने 'पीटीआई-भाषा' को दिए साक्षात्कार में कहा, कुछ गीत बहुत खराब हैं, और उनमें

लोकप्रिय गायकों की आवाज इस्तेमाल की गई है। इसे नियंत्रित करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अराजकता फैल जाएगी।

उन्होंने कहा कि एआई प्रौद्योगिकी के नैतिक उपयोग के लिए नियम होना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, इसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू हैं, और अच्छी चीजों का इस्तेमाल उन लोगों को सशक्त बनाने के लिए किया जाना चाहिए, जिन्हें कभी अपने विजन को अमल में लाने का मौका नहीं मिला। लेकिन इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना हमारे लिए बुरा है।

यह ऑक्सीजन में जहर मिलाने और उसे सांस के साथ अंदर लेने जैसा है। उन्होंने कहा, नियम होने चाहिए, जैसे कि कुछ चीजें आप नहीं कर सकते। जैसे, समाज में नैतिकता या व्यवहार के बारे में बात की जाती है, सॉफ्टवेयर और डिजिटल दुनिया में भी ऐसा होना चाहिए।

8 दक्षिण भारत राष्ट्रमत
www.dakshinbharat.com
epaper.dakshinbharat.com
RNI No. : TNHIN/2013/52520
Regn No. : TN/CCN/613/2014-2016
posted at Patrika Channel,
Egmore RMS, Chennai-8

जाति, भाषा, प्रांत और संप्रदायों का भेदभाव इतना जहरीला होता है कि वह न्याय, नीति, मानवता और कर्तव्य का बोध कभी नहीं होने देता। इनके बलबूते पर अयोग्य भी सत्ता की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। नीति शास्त्र कहता है कि अयोग्य के पास आई हुई सत्ता, सामर्थ्य और शक्ति सदैव लोगों के शोषण तथा उत्पीड़न का ही काम करती है। कमोबेश हम अपने देश के अनेक प्रांतों में और विश्व के अनेक देशों में यही स्थिति देख रहे हैं। यह कलयुग की करुण दर्दनाक कथा है।

# पांडिचेरी विश्वविद्यालय के कुलपति ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पुदुचेरी। पांडिचेरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पी. प्रकाश बाबू ने गुरुवार को नई दिल्ली में भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से शिष्टाचार भेंट की।

प्रो. पी. प्रकाश बाबू ने विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों तथा इसके परिसरों में विभिन्न विकासों और शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी दी तथा मशिक्षा मंत्री से सहयोग, सलाह और पांडिचेरी विश्वविद्यालय के संभावित दौरे का भी अनुरोध किया। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पांडिचेरी विश्वविद्यालय की विजिटर के रूप में पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की संविधि 1(ए) के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करके प्रोफेसर फनिति प्रकाश बाबू को पांडिचेरी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया। तदनुसार, प्रोफेसर प्रकाश बाबू ने 17 मार्च को पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी के कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था।

# तमिलनाडु सर्कल मध्य डाक क्षेत्र ने जागरूकता हेरिटेज वॉक का आयोजन किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। केंद्रीय डाक क्षेत्र, तमिलनाडु सर्कल के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में अरियालुर, कुड्डालोर, चिदंबरम, करूर, कराईकल, कल्लाकुरिची, मयिलादुथुराई, नागपट्टनम, पुदुकोट्टई, परम्बलुर, तिरुचिरापल्ली, तंजावुर और तिरुवरुर के 13 जिले शामिल हैं। इन जिलों में कई ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्मारक और स्थल हैं। इन स्मारकों और स्थलों का रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है या उन्हें तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों के रूप में घोषित किया गया है या हिंदू धर्म और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआरएंडसीई), तमिलनाडु राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं। ये स्मारक और स्थल पूर्वयुग के इतिहास, संस्कृति और जीवन शैली के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। हमारे देश के जिम्मेदार नागरिक के रूप में इन स्मारकों के लोकाचार को समझना हमारा कर्तव्य है और साथ ही इन स्मारकों और स्थलों की समृद्ध संस्कृति का अनुभव करने में सक्षम होना हमारे लिए बड़े सौभाग्य और सम्मान की बात है। इन ऐतिहासिक स्थलों के प्रति अपने कर्मचारियों की जागरूकता बढ़ाने के लिए, केंद्रीय डाक क्षेत्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) जैसे सरकारी संगठनों और कई गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम और स्कूली छात्रों के लिए आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करता है।

ऐसी ही एक पहल, हेरिटेज वॉक का आयोजन पुदुकोट्टई जिले के कोडुम्बलूर में मुचुकुंदेश्वर मंदिर, मूवरकोइल और ऐवरकोइल के ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थलों पर किया गया। एएसआई की सहायक अधीक्षक वेत्री सेल्वी और मुथु कुमार इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ शामिल हुए और इन स्थलों के बारे में अपनी जानकारी साझा की। इस पहल में भाग लेने वाले मध्य क्षेत्र टीएन सर्कल के कर्मचारी ऐसी शैक्षिक यात्रा का हिस्सा बनकर खुश थे और उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों और बच्चों के साथ प्राप्त ज्ञान को साझा करने की शपथ ली ताकि उन्हें हमारी समृद्ध संस्कृति और विरासत के बारे में पता चले। पोस्टमास्टर जनरल मध्य क्षेत्र तमिलनाडु की टी. निर्मला देवी आदि अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

# ज्ञानमुनि दीक्षा स्वर्ण जयंती पर होगा ओस्तवाल और बोहरा का सम्मान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। आचार्य हस्ती के शिष्य श्रमणसंघीय संत, रोचक व्याख्यानी ज्ञानमुनिजी की दीक्षा स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में तीर्थंकर महावीर ज्ञान ट्रस्ट का गठन किया गया है। रिखबचंद बोहरा को अध्यक्ष, डॉ. दिलीप धींग को मंत्री और महावीरचंद कोठारी को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। शांतिलाल सिंघवी संरक्षक तथा सुनील पालगोता, गजेश अबानी आदि को सदस्य बनाया गया है।

डॉ. दिलीप धींग ने बताया कि ज्ञानमुनि दीक्षा स्वर्ण जयंती समारोह 11 मई को श्रीरामपुर बेंगलूरु में मनाई जाएगी। समारोह में मोक्षद्वार ज्ञान पत्रिका के संपादक गौतमचंद ओस्तवाल एवं कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के संयोजक शांतिलाल बोहरा को ज्ञान आराधक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शास्त्रीय अध्यापन और स्वाध्याय प्रचार में सुदीर्घ योगदान के लिए रजत सम्मान-पत्र और 51 हजार रुपये की सम्मान-राशि से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, खैरताबाद के सौजन्य से किया जाएगा।

# रजत की महिला विंग 'गणगौर' का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। स्थानीय राजस्थानी एसोसिएशन(रजत) तमिलनाडु की महिला विंग गणगौर का स्थापना समारोह बुधवार को एक होटल में मनाया गया जिसमें चेयरपर्सन ममता अग्रवाल और उनकी वर्ष 2025-26 की टीम का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि डीजीपी(सेवानिवृत्त) के रूप में अर्चना रामसुंदरम तथा सिने पार्श्व गायिका श्रीलेखा पार्थसारथी उपस्थित थीं। मुख्य अतिथि एवं अन्य पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अध्यक्षा रेखा सिंघी ने में उनके कार्यकाल में हुए कार्यक्रमों की जानकारी आडियो विजुवल शो द्वारा दी तथा सहयोग देने वाले सभी जनों को धन्यवाद दिया।

इस अवसर पर रजत के अध्यक्ष नरेंद्र श्रीश्रीमाल, सचिव दिनेश कोठारी, पूर्वाध्यक्ष प्रवीण टाटिया, गणगौर के संयोजक विनोद जैन आदि उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि ने चेयरपर्सन ममता अग्रवाल, सहचेयरपर्सन कंचन बिसानी और उनकी टीम को शपथ ग्रहण करवाई। गणगौर के समन्वयक के रूप में अजय नाहर और सह समन्वयक ज्ञानचंद कोठारी को नियुक्त किया गया। शालिनी अग्रवाल ने मुख्य अतिथि का और सुनीता जैन ने विशेष अतिथि का परिचय दिया। दोनों अतिथियों का सम्मान किया गया। गणगौर की सदस्याओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

# अलसूर संघ में आयोजित बाल शिविर में 90 बच्चों ने लिया धार्मिक ज्ञान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ अलसूर द्वारा बच्चों के लिए आयोजित धार्मिक शिक्षण शिविर सम्पन्न हुआ। महावीर भवन में संघ के अध्यक्ष धनपतराज बोहरा की अध्यक्षता में आयोजित समापन समारोह में स्वाध्यायी गौतमचंद मकाना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। शिविर अध्यापिका राजेश्वरी तातेड़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस शिविर में 90 बच्चों ने 10 दिन तक धार्मिक ज्ञान ग्रहण किया और 9 जनों ने अध्यापन सेवाएं दी।

अलसूर संघ की ओर से मंत्री अभयकुमार बांठिया ने अतिथि का स्वागत करते हुए कहा कि स्वाध्याय संघ निरंतर ज्ञान मार्ग में सेवा कर रहा है। शिविर में बच्चों के अनुशासन को देखते हुए अध्यापकों को प्रेरणा दी कि वे तीन तीन बच्चों को ज्ञानार्जन कराने गोद ले और इन बच्चों को ज्ञान के साथ साथ धार्मिक संस्कार व व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाएं ताकि ऐसे बच्चों का समग्र विकास हो सके। मुख्य अतिथि गौतमचंद मकाना ने शिविर की सफल समाप्ति पर बच्चों को लगातार ज्ञान सीखते रहने की प्रेरणा दी। आशा बोहरा, सूरजबाई छाजेड़, राजूबाई बोहरा, सिमरन जैन, मधु मकाना, राजेश्वरी तातेड़, सुमित्रा सांखला, मंजू लोढ़ा एवं किरणबाई गादिया ने अध्यापन सेवा दी। अध्यक्ष धनपतराज बोहरा ने मंगलपाठ प्रदान किया।

# दक्षिण रेलवे ने 134वीं अंबेडकर जयंती मनाई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। दक्षिण रेलवे ने मंगलवार को दक्षिण रेलवे मुख्यालय में भारत रत्न डॉ. बी.आर. अंबेडकर की 134 वीं जयंती मनाई। डॉ. बी.आर. अंबेडकर एक दूरदर्शी नेता, विधिवेत्ता और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे, जिनकी विरासत आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। अंबेडकर जयंती हर साल अप्रैल के महीने में मनाई जाती है, ताकि भारतीय समाज में उनकी विरासत और योगदान को याद किया जा सके। समारोह के दौरान दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक आरएन सिंह ने डॉ. अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। अपर महाप्रबंधक कौशल किशोर, प्रमुख विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों/एसोसिएशनों के सदस्यों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया और भारतीय संविधान के निर्माता को श्रद्धांजलि दी। बाद में शाम को महाप्रबंधक ने दक्षिण रेलवे मुख्यालय के कर्मचारियों और बच्चों के लिए 134 वीं अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित निबंध और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार और योग्यता प्रमाण पत्र वितरित किए।

# टी दासरहल्ली आईमाता बडेर के पदाधिकारियों को किया आमंत्रित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। स्थानीय टी दासरहल्ली आईमाता बडेर में आयोजित कार्यक्रम में लग्गेरे बडेर के पदाधिकारियों ने नवनिर्मित आईमाता बडेर के प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए सीरवी समाज टी दासहल्ली के पदाधिकारियों को आमंत्रण पत्रिका देकर आमंत्रित किया। लग्गेरे बडेर के सचिव चेनाराम चोयल ने बताया कि चार दिवसीय प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 4 जून से धर्मगुरु दीवान माधवसिंह के सान्निध्य में होगा। इस मौके पर लग्गेरे बडेर के कार्यकारिणी सदस्य सेसाराम सेपटा,चूनाराम भायल, बिनजाराम आगलेचा, नेमाराम बर्फा और टी.दासरहल्ली बडेर के अध्यक्ष धर्मीचंद सोलंकी, कोषाध्यक्ष रमेशचन्द्र सातपुरा, पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मणराम लचेटा एवं मंदिर के पुजारी राजूराम सहित अनेक सदस्य उपस्थित थे।

# 'सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव' की वेबसाइट का हुआ उद्घाटन

## गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया उद्घाटन

पणजी/गोवा/दक्षिण भारत। सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत बाला आठवले के 83वें जन्मोत्सव तथा संस्था के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में गोवा में तीन दिवसीय 'सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव' का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव की अंग्रेजी वेबसाइट SanatanRashtraShankhnad.in का उद्घाटन गोवा राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के करकमलों से उनके मुख्यमंत्री कार्यालय में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वेबसाइट का अवलोकन किया और महोत्सव के लिए शुभकामनाएं दीं। इस समय 'सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव' की स्वागत समिति के पृथ्वीराज हजारे, सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता चेतन राजहंस, हिन्दू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे, साथ ही नारायण नाडकर्णी, मधुसूदन कुलकर्णी एवं अधिवक्ता राजेश गावकर उपस्थित थे।

इस वेबसाइट पर महोत्सव से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी गई है। वर्तमान में, वेबसाइट पर सनातन राष्ट्र का उद्देश्य, श्रीकृष्ण के शंखध्वनि प्रतीक के माध्यम से उसका संदेश, संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत बाळा आठवलेका परिचय, संस्था की जानकारी, संत-महंतों की जानकारी, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सूची, सांस्कृतिक कार्यक्रमों व लोककलाओं के प्रतिनिधिक चित्र प्रदर्शित किए गए हैं।

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.